सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 139, नई दिल्ली । मंगलवार, 30 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 मौत के कोचिंग सेंटर समेत हादसों में डूबा है पूरा सिस्टम
06 स्व-निर्देशित शिक्षा के लाभ
08 भगवान शिव ही सत्य, अनंत, अनादि, ओंकार शक्ति हैं

क्या भारत सरकार के बजट में घोषित, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा जारी गैजट नोटीफिकेशन, पॉलिसी, आदेशों, एडवाइजरी, दिशा निर्देशों की अवहेलना कर अपनी मर्जी चलाना ही परिवहन विभाग दिल्ली का कार्य है और कोई पूछने वाला नहीं, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। क्या भारत सरकार के बजट में घोषित, सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा जारी गैजट नोटीफिकेशन, पॉलिसी, आदेशों, एडवाइजरी, दिशा निर्देशों की अवहेलना कर अपनी मर्जी चलाना ही परिवहन विभाग दिल्ली का कार्य है और कोई पूछने वाला नहीं, बड़ा सवाल?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय दिल्ली और मुख्य सचिव आखिर क्यों अपनें आंख कान बंद कर के परिवहन विभाग को जनता को बिना वजह परेशान करने के लिए नही पूछ रहा है, क्या उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश की अवहेलना जुर्म नही !

क्या बजट में पेश दिशा निर्देश की अवहेलना करना जुर्म नही,

क्या सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गैजट नोटीफिकेशन/एडवाइजरी/ दिशा निर्देश की अवहेलना जुर्म नही ?

क्या उच्च न्यायालय के आदेश/ दिशा निर्देश की अवहेलना करना जुर्म नही ?

क्या महिला सुरक्षा में सेंध लगवाना जुर्म नही ?

क्या असेवधानिक ढंग से राजस्व वसूली जुर्म नही ?

बिना सेवा प्रदान करे किसी कम्पनी को अपने बल का दुरूपयोग कर फीस का नाम लेकर पैसा दिलवाना क्या जुर्म नही ?

उच्च पद पर आसीन होकर अपने निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना क्या जुर्म नही ?

इतना सब होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा सु मोटो ना उठाना और मुख्य सचिव एवम्-उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा भी सवाल जवाब ना उठाना किस तरह से जनहित है, बड़ा सवाल ?

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भुवनेश्वर में एक बार फिर मालगाड़ी पटरी से उतर गई

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर: भुवनेश्वर में एक बार फिर मालगाड़ी पटरी से उतर गई है. रेलवे से 8 डिब्बे गिर गए हैं. इसके चलते ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है. जानकारी के मुताबिक, आज सुबह 4:30 बजे मंचेश्वर रेलवे स्टेशन लेबल क्रॉसिंग के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस घटना के बाद से भुवनेश्वर से कटक और कटक से भुवनेश्वर जाने वाली सभी ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं। कई दिनों से ट्रेनें पटरी से उतरी हुई हैं और एक बड़ी टीम मौके पर पहुंच गई है और देर रात तक काम कर रही है. रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी.

गौरतलब है कि बीते 26 तारीख को सीमेंट से लदी यह मालगाड़ी सुबह करीब 8:40 बजे उस वक्त पटरी से उतर गई थी, जब वह कटक जा रही थी. ट्रेन का एक वैगन पूरी तरह से पटरी से उतर गया. दूसरा वैगन आधा ट्रैक पर था जबकि आधा नीचे गिर गया। सौभाग्य से, आस-पास की यात्री रेल पटरियों या यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। खबर मिलते ही ईस्ट कोस्ट रेलवे ने युद्धकालीन आधार पर पुनर्प्राप्ति कार्य शुरू कर दिया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. मध्य लाइन और अप लाइन सुरक्षित होने के कारण यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई, हालांकि, कुछ समय के लिए भुवनेश्वर स्टेशन पर यातायात की समस्या रही। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच दहशत का माहौल था. वैगनों को ट्रैक पर दोबारा खड़ा करने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो गई। रात की ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण स्पष्ट नहीं है. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहा कि जांच जारी है।

बस मार्शलों को एलजी आफिस से डिटेंन किया

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। पिछले 9 महीने से ड्यूटी से बाहर निकाले गए 10792 डीटीसी बस मार्शलों का सोमवार को सब्र का बांध टूट गया। वह पिछले नौ महीने से दिल्ली सचिवालय की सडक पर धरने पर बैठे थे। लेकिन कोई भी सरकारी अमला इनकी सुध लेने नहीं आया।इस बीच वह दिल्ली सरकार के तमाम मन्त्री से लेकर संतरी तक और भाजपा के भी नेताओ से मिल कर हल निकालने की बात कर नौकरी बहाल करने की बात रख चुके हैं। मगर मार्शलों का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बस मार्शलों को छला है। वह एक दूसरे के ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ते रहे है। इस बाबत मुकेश मार्शल संगम विहार ने बताया कि बेरोज़गर हुए बस मार्शलों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 20 मार्शलों ने खुदकुशी तक कर ली है। गरीबी, भुखमरी, और बेरोजगारी से परेशान हजारो बस मार्शलों ने सोमवार को उपराज्यपाल आफिस में अपना दुख बताने और नौकरी बहाल करने की गुहार करने गए तो वहां भी मार्शलों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। बडी संख्या में एलजी आफिस पहुंचे महिला, पुरूष बस मार्शलों को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेंन कर लिया गया। खबर लिखे जाने तक मार्शलों का नेतृत्व कर रहे संजय शर्मा, प्रेमजीत, सचिन ,समेत मुकेश संगम विहार ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने तमाम बस मार्शलो को डिटेंन कर बस में भर लिया है और वह उन्हे किसी अननाऊन जगह पर ले जा रहे थे।संजय शर्मा ने बताया कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार है। जब तक तमाम बस मार्शलों का रोजगार बहाल नहीं किया जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

नए स्क्रैपिंग सेंटर की बाट जोह रहे 1.73 लाख वाहन

नोएडा। नए स्क्रैपिंग सेंटर के लिए जिले के 1.73 लाख वाहन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह वे वाहन हैं जो अपना निर्धारित समय पूरा कर चुके हैं। इनमें 10 वर्ष की आयु पुरी कर चुके डीजल के 1.36 लाख वाहन हैं। वहीं 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले करीब 47 हजार वाहन भी इसमें शामिल हैं। अहम है कि जिले में केवल दो स्क्रैपिंग सेंटर होने की वजह से इन वाहनों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि एनजीटी के नियम के अनुसार निर्धारित समय पूरा कर चुके डीजल व पेट्रोल वाहन एनसीआर में संचालित नहीं हो सकते हैं। ऐसे में वाहन मालिकों को इन्हें या तो स्क्रैप कराना होगा या ऐसे जिलों व राज्यों में ट्रांसफर कराकर ले जाना होगा, जहां पर एनजीटी का नियम लागू न होता हो। विभाग के अनुसार, जिले के ज्यादातर वाहन स्वामी अपने वाहन किसी अन्य जिले में भेजने के बजाय उन्हें स्क्रैप कराने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक माह में ऐसे 300 वाहनों को ही लोग ट्रांसफर कराकर अन्य जिलों में ले जा रहे हैं, लेकिन स्क्रैप कराने वालों की संख्या साढ़े छह हजार है।

आसानी से बन जाता है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन कागजात को रखें तैयार, ऐसे करें अप्लाई

वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र का खो जाना, वाहन मालिक को बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। लेकिन डुप्लिकेट आरसी हासिल करना बहुत आसान है। डुप्लिकेट आरसी हासिल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा।

एक समय था जब गाड़ी की RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पंजीकरण प्रमाणपत्र) (आरसी) किताब के तौर पर आती थी। फिर यह एक प्रिंटेड पेपर के रूप में आई। और अब यह महज एक कार्ड है। वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है। और वह है आरसी का खो जाना। हालांकि यह वाहन मालिक को बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। लेकिन डुप्लिकेट आरसी हासिल करना बहुत आसान है। डुप्लिकेट आरसी हासिल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा। और इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

डुप्लिकेट आरसी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और सुनिश्चित करें कि नीचे बताए जा रहे कागजात आपके पास तैयार रखें हैं।

इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

नुकसान के सबूत के लिए एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी
फॉर्म 26 (आरटीओ में उपलब्ध)
खोई हुई आरसी की कॉपी
वैध बीमा प्रमाणपत्र
कमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स क्लीयरेंस
पहचान प्रमाण पत्र
मौजूदा पता का प्रमाण
पीयूसी प्रमाणपत्र
इंजन और चेसिस नंबर का पेंसिल मार्क

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले, व्यक्ति को परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। "ऑनलाइन सेवाएं" टैब के अंतर्गत, ₹वाहन संबंधी सेवाएं₹ पर क्लिक करें। फिर वेबसाइट उस राज्य का नाम पूछेगी जिसमें व्यक्ति को अपने राज्य को चुनना होगा। मिसाल के लिए अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको दिल्ली को चुनना है। इसके बाद वेबसाइट दिल्ली के वाहन परिवहन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगी।

फिर एक पॉप-अप अपने आप खुल जाएगा जिसके जरिए व्यक्ति को ₹डुप्लिकेट आरसी जारी करना₹ पर क्लिक करना होगा जो ₹वाहन सेवा₹ के अंतर्गत होगा। व्यक्ति को पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी या यदि उसके पास पहले से ही एक खाता है तो उसे लॉग-इन करना होगा। एक बार लॉग-इन हो जाने के बाद, ₹ऑनलाइन सेवाएं₹ के तहत, ₹वाहन संबंधी सेवाएं₹ के लिए एक ऑप्शन मिलता है।

अगला स्टेप वाहन की डिटेल्स भरना है। व्यक्ति को पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर भरना होगा। फिर आधार नंबर और ओटीपी भरकर वेरिफिकेशन पूरा करें। सफलतापूर्वक ऐसा करने के बाद, स्क्रीन कई ऑनलाइन सेवाओं की पेशकश करेगी जिसका व्यक्ति लाभ उठा सकता है। ₹डुप्लिकेट आरसी का मुद्दा₹ विकल्प चुनें और सबमिट करें दबाएं। अगला कदम एक फॉर्म भरना है, जिसके बाद एक सर्विस रिक्वेस्ट (सेवा अनुरोध) जेनरेट होगा।

इसके बाद ई-हस्ताक्षर करने और दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है। फिर आपको ई-केवाईसी पूरा करना होगा और भुगतान करना होगा। एक बार जब आरटीओ आवेदन को मंजूरी दे देता है तो वे स्पीड पोस्ट के जरिए डुप्लीकेट आरसी भेज देंगे।

डुप्लीकेट RC ऑफलाइन कैसे हासिल करें

डुप्लीकेट आरसी ऑफलाइन हासिल करने के लिए, सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी आरटीओ पर जाना होगा। और फॉर्म 26 भरना होगा जिसमें वाहन संख्या, इंजन संख्या, चेसिस नंबर आदि जैसे डिटेल्स की आवश्यकता होती है। फिर से, सभी डिटेल्स की दोबारा और यदि जरूरी हो, तो तीन बार जांच करें।

इसके बाद, सभी जरूरी सहायक दस्तावेज संलग्न करें, फीस का भुगतान करें, और सभी जरूरी कागजी जमा करें। एक बार यह सब काम पूरा हो जाने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जिसे ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

लग सकता है समय

डुप्लिकेट आरसी बनवाने में कारण और किसी विशेष आरटीओ में कितने आवेदन किए गए हैं, इस बार पर निर्भर करते हुए समय लग सकता है। इसलिए इसमें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है।

दिल्ली से हरियाणा के गुभाना-माजरी तक चलेंगी डीटीसी बसें : गहलोत

परिवहन विशेष न्यूज

बादली। दिल्ली से हरियाणा के गुभाना और माजरी गांव को जोड़ने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की बस सेवा शुरू करने के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। जल्द ही यहां बस सेवा शुरू होने की उम्मीद है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुभाना गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सीमा से लगते हरियाणा के गांवों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए भी सक्रिय है। मास्टर रणबीर गुलिया की मांग पर उन्होंने बस सेवा शुरू करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि एक सप्ताह में बस शुरू होगी, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब हरियाणा में भी लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है।

इससे पहले गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मंत्री गहलोत का स्वागत किया। कई युवाओं ने आप पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। उनके साथ मास्टर रणबीर गुलिया ने कहा कि स्थानीय युवाओं का प्रतिदिन दिल्ली में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है। लोगों की जरूरत के हरियाणा सरकार की ओर से कोई बस सेवा शुरू नहीं की गई है। अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ग्रामीणों की मांग पर सर्वे कार्य करवाने के बाद बस सेवा दिल्ली के तिलक नगर तक एक सप्ताह में शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री का गांव में पहुंचने पर स्वागत किया।

दो किलोमीटर दूर है गुभाना-माजरी

दिल्ली की बाक्करगढ़ सीमा से गुभाना और माजरी गांव दो किलोमीटर दूर है। दोनों ही गांवों से दिल्ली के लिए कोई बस सेवा नहीं है। लोगों को ऑटो या निजी वाहनों से ही आना-जाना पड़ता है। बस सेवा शुरू होने से कई गांवों को इसका लाभ होगा।

डॉ. लॉजिस्टिक्सः लॉजिस्टिक्स के महत्व को समझने की पहल - डॉ. अंकुर शरण

डॉ. लॉजिस्टिक्स एक महत्वपूर्ण पहल है जो लॉजिस्टिक्स की कार्यप्रणाली और इसके महत्व को आम जनता तक पहुँचाने का उद्देश्य रखती है। इस रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स के बुनियादी पहलुओं को संक्षेप में समझाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे यह हमारे दैनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लॉजिस्टिक्स, सामग्री और सेवाओं के प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से व्यवसाय और समाज की दक्षता को बढ़ाता है। यह हमारे जीवन की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएँ, और वस्त्र वितरण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

हमारी युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र की महत्वता को समझना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार हो सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। यह रिपोर्ट युवाओं को लॉजिस्टिक्स के महत्व से परिचित कराएगी और उनके करियर संभावनाओं को उजागर करेगी।

लॉजिस्टिक्सः हमारी दिनचर्या में महत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान

लॉजिस्टिक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में केवल माल की ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला की प्रक्रिया की छवि आती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स का हमारे दैनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है? चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं।

लॉजिस्टिक्स का दैनिक जीवन में उपयोग

1. खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाः हम रोज़ाना ताजे फल, सब्जियाँ और अन्य खाद्य सामग्री का सेवन करते हैं। यह सब कुछ लॉजिस्टिक्स की वजह से संभव होता है। खेतों से लेकर बाज़ार तक, और फिर हमारे घर तक, खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा और सही समय पर आपूर्ति लॉजिस्टिक्स द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है।

2. स्वास्थ्य सेवाएँः अस्पतालों में दवाएँ, उपकरण, और अन्य आवश्यक वस्तुएँ नियमित रूप से आपूर्ति की जाती हैं। अगर लॉजिस्टिक्स प्रणाली सटीक और प्रभावी न हो, तो चिकित्सा सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं, जो सीधे तौर पर हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

3. ऑनलाइन शॉपिंगः ई-कॉमर्स के ज़माने में, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने हमारी ज़िन्दगी को बहुत आसान बना दिया है। इस सुविधा के पीछे एक सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है, जो हमारे ऑर्डर को सही समय पर हमारे दरवाजे तक पहुंचाता है।

4. रोज़मर्रा की वस्तुएँः घर की रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए जैसे कपड़े, किचन सामान, और अन्य वस्तुएँ भी लॉजिस्टिक्स के माध्यम से ही हमारे हाथ तक पहुँचती हैं।

लॉजिस्टिक्स और राष्ट्र निर्माण

1. आर्थिक विकासः एक सुगम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह व्यापार को सरल और सस्ता बनाता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ और औद्योगिक विकास तेजी से होते हैं।

2. प्रशासन और आपातकालीन सेवाएँः प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्यों की त्वरित आपूर्ति लॉजिस्टिक्स पर निर्भर होती है। इसके बिना, राहत और पुनर्वास कार्यों में विलंब हो सकता है, जिससे लोगों की ज़िन्दगियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षाः लॉजिस्टिक्स सेना और सुरक्षा बलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सैन्य उपकरण, आपूर्ति, और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सही समय पर आपूर्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

4. सामाजिक समरसताः सही और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ, लॉजिस्टिक्स स्थानीय और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाता है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में समान विकास संभव होता है।

लॉजिस्टिक्स केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है जो हमारे दैनिक जीवन को सुगम बनाती है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके प्रभावी प्रबंधन से हम न केवल एक विकसित और सुरक्षित राष्ट्र की दिशा में बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। इसलिए, लॉजिस्टिक्स के महत्व को समझना और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना हमारे समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अखबारों की दुनिया में लॉजिस्टिक्स का अहम योगदान

हमारी दिनचर्या में अखबारों का महत्वपूर्ण स्थान है। हर सुबह, अखबार हाथ में लेकर हम ताजे समाचारों, विचारों और विश्लेषणों से रूबरू होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अखबारों तक पहुँचने की प्रक्रिया कितनी जटिल और महत्वपूर्ण होती है? अखबारों का वितरण लॉजिस्टिक्स पर पूरी तरह निर्भर करता है। आइए, इस लेख में समझते हैं कि अखबारों के वितरण में लॉजिस्टिक्स का क्या योगदान होता है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है।

लॉजिस्टिक्स का अखबार वितरण में योगदान

1. सामग्री की आपूर्ति और प्रबंधन

अखबार के उत्पादन की प्रक्रिया में कई सामग्री शामिल होती हैं - कागज, स्याही, और अन्य आवश्यक वस्तुएँ। लॉजिस्टिक्स यह सुनिश्चित करता है कि इन सभी सामग्री की सही मात्रा और गुणवत्ता समय पर उपलब्ध हो। कागज और स्याही का उचित स्टॉक और आपूर्ति सुनिश्चित करना अखबार के सही समय पर प्रिंट और वितरण के लिए आवश्यक है।

2. प्रिंटिंग और प्रसंस्करण

अखबारों की प्रिंटिंग और प्रसंस्करण के दौरान भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अहम होती है। प्रिंटिंग प्रेस में सामग्री का समय पर पहुंचना, मशीनों की मरम्मत और रखरखाव, और प्रिंटिंग के बाद के प्रसंस्करण कार्य सभी लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रबंधित होते हैं। एक सटीक और समय पर आपूर्ति श्रृंखला अखबारों की गुणवत्ता और तत्परता को सुनिश्चित करती है।

3. वितरण और पहुंच

अखबारों की प्रमुख चुनौती उनका वितरण है। सुबह के समय ताजे समाचारों की पहुंच के लिए तेज़ और सटीक वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक्स वितरण की योजना, मार्ग निर्धारण, और ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। इसमें वितरण वाहनों का प्रबंधन, डिलीवरी पर्सन की नियुक्ति, और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि अखबार सही समय पर सही जगह तक पहुँचे।

4. क्षेत्रीय और स्थानीय वितरण

अखबारों की विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण की योजना भी लॉजिस्टिक्स द्वारा बनायी जाती है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अखबारों का वितरण करना चुनौतीपूर्ण होता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्रीय और स्थानीय वितरण नेटवर्क का निर्माण करता है जो अखबारों को हर घर तक पहुँचाने में मदद करता है।

5. आपातकालीन और विशेष वितरण

कभी-कभी, विशेष समाचारों या आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल वितरण की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक्स इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष संस्करणों, ब्रेकिंग न्यूज़, और इमरजेंसी अपडेट्स के लिए त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स के बिना अखबार वितरण का परिदृश्य

यदि लॉजिस्टिक्स प्रभावी न हो, तो अखबारों का वितरण प्रभावित हो सकता है। प्रिंटिंग सामग्री की आपूर्ति में विलंब, वितरण में देरी, और असंगठित वितरण नेटवर्क अखबारों की गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे न केवल अखबार उद्योग को हानि होती है, बल्कि पाठकों की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

अखबारों का वितरण केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है; यह एक जटिल और समन्वित लॉजिस्टिक्स प्रणाली पर निर्भर करता है। सामग्री की आपूर्ति, प्रिंटिंग, वितरण और क्षेत्रीय नेटवर्क का प्रभावी प्रबंधन अखबारों की गुणवत्ता और समय पर पहुंच सुनिश्चित करता है। इसलिए, अखबारों के विश्वसनीय वितरण के पीछे जो लॉजिस्टिक्स प्रणाली काम करती है, उसका महत्व समझना और सराहना अत्यंत आवश्यक है। लॉजिस्टिक्स की सही योजना और कार्यान्वयन से ही हम हर सुबह ताजे और सटीक समाचार प्राप्त कर सकते हैं।

लॉजिस्टिक्स को समझना और इसके मुख्य बिंदुओं को जानना क्यों जरूरी है

लॉजिस्टिक्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर पहलू को प्रभावित करता है। इसके बुनियादी पहलुओं को समझना और इसके मुख्य बिंदुओं को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। आइए विस्तार से जानें कि लॉजिस्टिक्स को समझना क्यों जरूरी है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं:

1. रोजमर्रा के जीवन में सुगमता

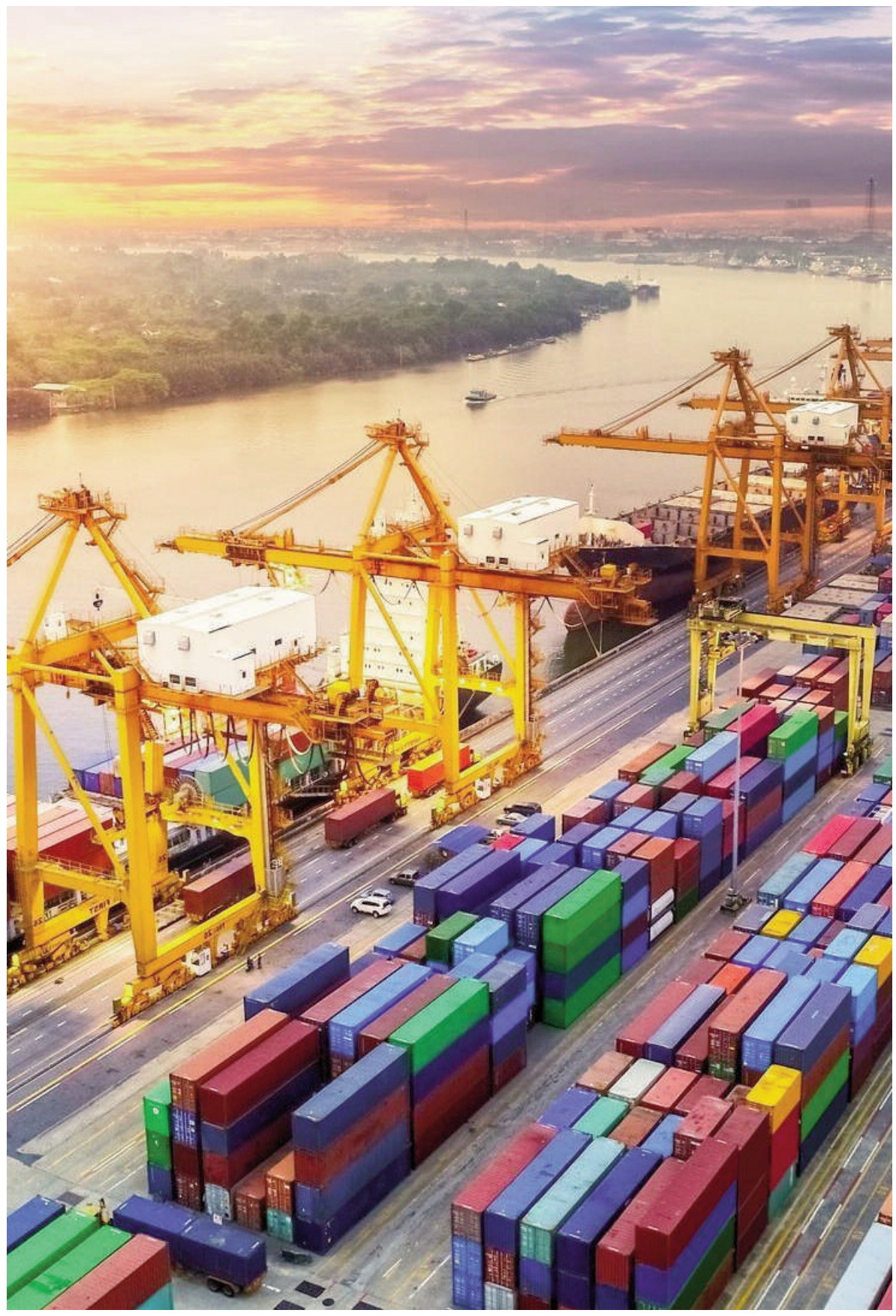

क्यों जरूरी है:

समय की बचतः लॉजिस्टिक्स के माध्यम से सामान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिससे हमें बाजार में मिलने वाली वस्तुओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है।

खाद्य आपूर्तिः ताजे खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करती है, जो हमारे आहार की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

2. आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा

क्यों जरूरी है:

लागत में कमीः प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रणाली से व्यवसायों को लागत कम करने में मदद मिलती है, जो उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है।

व्यापारिक अवसरः बेहतर लॉजिस्टिक्स से नई व्यापारिक संभावनाओं और अवसरों का निर्माण होता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

3. आपातकालीन स्थितियों और राहत कार्य

क्यों जरूरी है:

राहत कार्यः आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करते हैं।

सही समय पर आपूर्तिः दवाओं, खाद्य सामग्री और राहत सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना जीवन रक्षक हो सकता है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आपूर्ति

क्यों जरूरी है:

सैन्य आपूर्तिः सैन्य उपकरण और आपूर्ति की त्वरित और सटीक आपूर्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सुरक्षा बलों की तैयारियाँः लॉजिस्टिक्स प्रणाली सुरक्षा बलों की तैयारियों और संचालन की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है।

5. सामाजिक और क्षेत्रीय विकास

क्यों जरूरी है:

सामाजिक समरसताः सही और समय पर आपूर्ति से विभिन्न क्षेत्रों के बीच समान विकास संभव होता है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।

उपलब्धता में सुधारः दूरदराज के क्षेत्रों में भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जिससे सभी क्षेत्रों का विकास हो सकता है।

6. पर्यावरणीय प्रभाव

क्यों जरूरी है:

निरंतरता और स्थिरताः लॉजिस्टिक्स के माध्यम से वस्तुओं की उचित भंडारण और परिवहन से पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

संसाधनों की बचतः प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रणाली संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से फायदेमंद है।

7. नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग

क्यों जरूरी है:

प्रौद्योगिकी में सुधारः लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग त्वरित और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करता है।

डाटा एनालिटिक्सः लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में डाटा एनालिटिक्स का उपयोग निर्णय लेने में सहायक होता है और संचालन को बेहतर बनाता है।

लॉजिस्टिक्स को समझना और इसके मुख्य बिंदुओं को जानना न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न पहलुओं को एकजुट करता है और आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए, लॉजिस्टिक्स के महत्व को समझना और इसे प्रभावी रूप से लागू करना सभी के लिए फायदेमंद है।

लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर है?

लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही महत्वपूर्ण संचालन प्रबंधन क्षेत्र हैं, लेकिन इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो उनकी भूमिकाओं और कार्यों को अलग करते हैं। आइए, विस्तार से समझें कि इन दोनों में क्या अंतर हैः

1. परिभाषा

लॉजिस्टिक्सः लॉजिस्टिक्स एक व्यापक प्रबंधन प्रक्रिया है जो माल, सेवाओं, और सूचनाओं की योजना, कार्यान्वयन और नियंत्रण को शामिल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सही समय पर सही स्थान पर सही वस्तुएँ पहुंचाना है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला के सभी घटक जैसे भंडारण, वितरण, आपूर्ति की योजना, इन्वेंट्री प्रबंधन, और ग्राहक सेवा शामिल हैं।

ट्रांसपोर्टेशनः ट्रांसपोर्टेशन एक विशेष प्रक्रिया है जो माल या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करती है। यह लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसका ध्यान मुख्य रूप से यात्रा के साधनों, मार्गों और तरीकों पर केंद्रित होता है।

2. दायरा

लॉजिस्टिक्सः

सम्पूर्ण प्रबंधनः लॉजिस्टिक्स की प्रक्रिया में सामग्री की प्रबंधन, वितरण की योजना, भंडारण, और इन्वेंट्री प्रबंधन शामिल हैं।

संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाः यह एक संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जैसे कि स्रोत से लेकर अंतिम ग्राहक तक।

ट्रांसपोर्टेशनः

साधन और मार्गः ट्रांसपोर्टेशन केवल माल या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक साधनों और मार्गों पर ध्यान केंद्रित करता है।

विशेष प्रक्रियाएँः इसमें वाहनों, जहाजों, विमानों, और अन्य परिवहन माध्यमों की योजना और प्रबंधन शामिल होता है।

3. उद्देश्य

लॉजिस्टिक्सः

समग्र प्रबंधनः लॉजिस्टिक्स का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियाँ प्रभावी ढंग से काम करें और संसाधनों का सही उपयोग हो।

सेवा गुणवत्ताः ग्राहक की संतुष्टि को सुनिश्चित करना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं को बेहतर बनाना।

ट्रांसपोर्टेशनः

परिवहन सुविधाः ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य उद्देश्य माल और व्यक्तियों को सुरक्षित और समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है।

मूल्य और दक्षताः परिवहन लागत को कम करना और यात्रा की दक्षता को बढ़ाना।

4. प्रबंधन

लॉजिस्टिक्सः

पारस्परिक समन्वयः लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे कि इन्वेंट्री प्रबंधन, गोदाम प्रबंधन, और आपूर्ति योजना को समन्वित करना शामिल होता है।

प्रक्रिया विश्लेषणः समग्र प्रक्रिया का विश्लेषण और सुधार करना।

ट्रांसपोर्टेशनः

वाहन और मार्गः ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधन में वाहनों, यात्रा की योजनाओं, और मार्गों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

लॉजिस्टिक्स का एक हिस्साः ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स का एक घटक है जो केवल परिवहन से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है।

5. उदाहरण

लॉजिस्टिक्सः

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधनः एक कंपनी जो माल की आपूर्ति, स्टोरेज, और वितरण को संपूर्ण तरीके से प्रबंधित करती है।

इन्वेंट्री प्रबंधनः एक रिटेल स्टोर जो स्टॉक का प्रबंधन करता है और उसे सही समय पर पुनः भरता है।

ट्रांसपोर्टेशनः

लोडिंग और शिपिंगः मालवाहक ट्रक द्वारा माल की ढुलाई और शिपमेंट का प्रबंधन।

विमान यातायातः एयरलाइन कंपनियों द्वारा यात्रियों और Cargo की उड़ान सेवाएँ।

लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन वे अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य करते हैं। लॉजिस्टिक्स एक व्यापक प्रबंधन प्रक्रिया है जो आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन विशेष रूप से माल या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। दोनों के बीच सही समन्वय से ही एक प्रभावी और कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सकती है।

डॉ. अंकुर शरणः लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नई पहल

डॉ. अंकुर शरण एक प्रमुख विशेषज्ञ और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक अग्रणी विचारक हैं। उनके नेतृत्व में लॉजिस्टिक्स के महत्व को आम जनता, विशेषकर युवाओं के बीच समझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक्स के बुनियादी पहलुओं और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग इस क्षेत्र की अहमियत को समझ सकें और इसके लाभों का सही मूल्यांकन कर सकें।

ankur.supplychain@gmail.com

मौत के कोचिंग सेंटर समेत हादसों में डूबा है पूरा सिस्टम

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर से लेकर फर्जी अस्पताल में आग से मौत, के साथ अवैध निर्माण, खतरनाक इमारत तले दबती निरीह जनता, वहीं नकली दवाए निगलते बीमार और नकली खाने- पीने की वस्तुओं से बेजार लोगो का अब सिस्टम से भरोसा उठने लगा है।बता दें कि शनिवार की बरसात ने ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित राव आईएएस बनाने वाली फैक्ट्री में बंद नालो और सीवर के पानी ने उक्त कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 12 फीट तक पनाह ले ली थी, अचानक तेज रफ्तार से बेसमेंट में घुसे पानी में वहां पढाई में मस्त 30 के करीब स्टूडेंट्स जल भीतर फंस गए थे। इनमें से तीन छात्र जिनमें दो लडकी और एक लडके जो अति जलभराव की वजह डूबने से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद राजधानी दिल्ली के नेता, सिविक ऐजेंसिया अचानक हरकत में आ गई। वहीं राजनीति भी अपने चर्म पर पहुंच गई। उसी के मद्देनजर भाजपा समेत आम आदमी पार्टी के नेताओ ने एक दूसरे के खिलाफ तबीयत से जहर उगलना शुरू कर दिया। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर अपनी भड़ास

निकाली। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर भड़ास निकाली। अब सवाल उठता है कि क्या इस हादसे में मौत पर ऐसी औछी और गंदी राजनीति करने के पीछे मुद्दो से भटकाने की कवायद भर है। ये बात सही है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में सभी कायदे कानून को ताक पर रख कर धडबा नुमा कोचिंग सेंटर्स में आईपीएस, आईएएस, समेत एसएससी और टीचर्स को तैयार किया जाता है। बता दें कि मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में 15 जून, 2023 को बिजली मीटर में शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। कोचिंग सेंटर में उस वक्त तीसरी मंजिल पर करीब 200-250 छात्र मौजूद थे। सीढियों के पास मीटर में लगी आग ने वहां पडे कबाड और गाडियों मे आग लग गई। आग ने उपर की मंजिलों को भी लपकना शुरू कर दिया। नीचे उतरने के तमाम रास्ते ब्लाक हो गए थे। कोचिंग सेंटर के तमाम छात्र-छात्राए खिडकी के रास्ते रस्सी के

सहारे नीचे उतरने लगे तभी हड़बड़ाहट में छात्रों के हाथों से रस्सी छूटी और वह नीचे जमीन पर आ गिरे। इस दुर्घटना में करीब 61 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जबकि इससे पहले 25 मई, 2023 की आधी रात को विवेक विहार स्थित बेबी केयर अस्पताल के नीचे आक्सीजन सिलेंडर भरने के दौरान सिलेंडर राकेट की तरह उडा और अस्पताल की दूसरी मंजिल में जा घुसा और फट गया। उस वक्त बेबी केयर सेंटर में नन्हें जन्में मासूमों को एडमिट किया गया था। एडमिट 12 बच्चों में से 7 नन्हें बच्चो की आग लगने से मौत हो गई थी।वह बेबी केयर अस्पताल अवैध तरीके से रिश्वतखोरी के बल पर धड्डुले से चल रहा था। इन दोनों मामलों में जांच की गई। अवैध और गैरकानूनी तरीके से दोनो जगह गतिविधियां पांई गई। कुछ दिन प्रशासन, पुलिस ने एक्शन तो लिया, लेकिन फिर सब चलता है के मिशन पर परशान ने आंखे मूंद ली और फिर कोर्ट और गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाते हुए शनिवार को राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेट में पानी भर गया। जिसमें तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद पुलिस, प्रशासन और राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कॉर्डिनेटर समेत कुल 7 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा सरकारी अमला एक्शन में आ गया है। सोमवार को औल्ड राजेन्द्र नगर के इलाके में बुलडोजर की कारवाई की गई है। राजनीति अपने चर्म पर है। मामला संसद तक जा पहुंचा है। धरना-प्रदर्शन जारी है। लेकिन मौत के इस कोचिंग सेंटर समेत कई अन्य मामलों में सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह से डूब चुका है और भ्रष्टाचार की जल समाधी में मग्न हो बेशर्मी वाले अंदाज में आ गए है कि ₹ये तो हादसों का शहर है₹ और इसी कडी में हादसे दर हादसे का सिलसिला जारी है। डूबिये कि आप दिल्ली में है।

भारत नेपाल संबंधों को मजबूती देने में राणा शिव शंकर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नेपाल सर्वेश्वर समूह काठमांडू के संरक्षक राणा शिव शंकर सिंह भाजपा के समर्पित नेता के तौर पर अपनी स्वच्छ एवं दमदार राजनीति के बदौलत नेपाल भारत संबंधों को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। राणा शिव शंकर सिंह नेपाल मामलों के विशेषज्ञ हैं। नेपाल में सरकार एवं माओवादी संघर्ष के दौरान 13 नवंबर 2005 को दिल्ली में हुई समझौता बैठक में राणा शिव शंकर सिंह ने भी भागीदारी निभाई थी। परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्वहाली का रास्ता साफ हुआ। जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पत्र लेकर डॉक्टर कर्ण सिंह शांति दूत के रूप में महाराज श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह से मिले। भारत नेपाल काला पानी लिपुलेख लिपि धुरिया जो भारतीय सेना का कैंप है, यहां नक्शा को लेकर जो नो मैन लैंड पर जो विवाद है उसको लेकर भी राणा शिव शंकर सिंह नेपाल के राष्ट्रपति एवं वहां के डिप्लोमेट्स के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि इस मसले का हल निकल जाने के बाद कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग से जाने का रास्ता साफ हो जाएगा जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।

कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की दूसरे दिन भी कार्रवाई

ओल्ड के राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत हो गई। सभी छात्र बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से डूब गए थे। इसके बाद से दिल्ली नगर निगम (MCD) अब अवैध रूप से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कर रहा है। रविवार और सोमवार को चली यह कार्रवाई अगले दिन भी जारी रहेगी।

नई दिल्ली। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) अब अवैध रूप से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कर रहा है। 13 सेंटर रविवार को सील करने के बाद सोमवार को भी सात कोचिंग सेंटर सील किए गए।

ओल्ड राजेंद्र नगर में छह कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। वहीं, उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट को सील किया गया। कार्रवाई में दृष्टि (द विजन) जैसे प्रमुख कोचिंग संस्थान शामिल हैं।

अवैध निर्माण भी किए गए ध्वस्त

एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को ओल्ड राजिंदर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाया। इस दौरान उन निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया जो बारिश के पानी के बहाव को रोक रही थीं। इन्हीं वजह इलाके में बाढ़ आ गई थी।

बेसमेंट का हो रहा गलत प्रयोग

एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने बताया कि सीलिंग अभियान दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी चलाया जाएगा। जहां कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बेसमेंट का प्रयोग लाइब्रेरी, क्लासेस या अन्य किसी कामों के लिए प्रयोग हो रहा है।

दायरे में आए प्रमुख कोचिंग सेंटर

दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि इसके अलावा मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट को भी सील कर दिया गया है, जहां हमने सीलिंग अभियान भी चलाया था। सोमवार को एमसीडी की जांच के दायरे में आए प्रमुख कोचिंग सेंटरों में दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजी राम और रवि आईएएस हब, राजेंद्र नगर में श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट और मुखर्जी नगर में दृष्टि (द विजन) शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि वाजी राम और रवि आईएएस हब की इमारत में तीन बेसमेंट को सील कर दिया गया है।

इस तरह गई तीनों छात्रों की जान

ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम सात बजे लगभग बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें अनुमति सिर्फ स्टोर चलाने की थी। शनिवार को भारी बारिश की वजह इमारत में शीशे का गेट टूटने के कारण बेसमेंट में पानी चला गया। गेट को नुकसान एक थार चालक की वजह से पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

बेसमेंट में 35 छात्र पढ़ रहे थे, इस दौरान तीन छात्रों को छोड़कर सभी बाहर आ गए। बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमैट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाने से बिजली भी चली गई। बिजली जाने की वजह से दरवाजे नहीं खुले और हादसे में दो छात्रा व एक छात्र अंदर फंसे रह गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

ये हैं तीनों छात्र

हादसे में मरने वाली एक छात्रा तान्या की पहचान उसी समय हो गई थी। वह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता तेलंगाना में इंजीनियर हैं। रविवार को दो अन्य की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर की श्रेया यादव व केरल के एर्नाकुलम के नेविन डाल्विन के रूप में हुई। ये तीनों राजेंद्र नगर में ही अलग-अलग पीजी में रहते थे।

ईडी का जवाब तैयार, लेकिन... सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, करना होगा इंतजार

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं मिली है। उन्हें जमानत पर के लिए अभी इंतजार करना होगा। मामले में कोर्ट फिर से पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

नईदिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। यह मामला सोमवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

जवाबी हलफनामा जल्द होगा दाखिल

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पीठ को बताया कि सीबीआई ने सिसोदिया की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा तैयार है और इसे जल्द ही दाखिल किया जाएगा।

16 महीने से जेल में सिसोदिया

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई और ईडी को सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि वरिष्ठ आप नेता 16 महीने से जेल में हैं और केस आगे नहीं बढ़ रहा है। अक्टूबर 2023 से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

धीमी गति से आगे बढ़ा मुकदमा तो...

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीने में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सिसोदिया की याचिकाओं पर आपत्ति

एएसजी राजू ने सिसोदिया की याचिकाओं पर प्रारंभिक आपत्तियां भी उठाईं और कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट के उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है। एक ही आदेश को दो बार चुनौती नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट के पहले आदेश को चुनौती

सिसोदिया ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने उन्हें उसी साल नौ मार्च को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

एलजी सक्सेना ने की मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की

राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के बाद एलजी वीके सक्सेना ने मृतकों के परिजनों को 10–10 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। एलजी ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मारे गए तीनों स्टूडेंट्स के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की।

राज निवास के एक बयान के अनुसार, दुखद घटना पर विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात करने वाले एलजी ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया।

टास्क फोर्स करेगी सभी इमारतों का सर्वेक्षण

बयान में कहा गया है कि 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई है। इस साल की शुरुआत में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत गठित एमसीडी और डीएफएस की एक संयुक्त टास्क फोर्स भी राजेंद्र नगर क्षेत्र की सभी इमारतों का सर्वेक्षण करेगी।

बयान में कहा गया है कि यह सभी बेसमेंट और अन्य अवैध संरचनाओं को सील करेगा जो बिल्डिंग बायलॉज, एमपीडी 2021 और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।

सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड ने युवा शक्ति मॉडल में अपना दूसरा पूर्ण दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड ने युवा शक्ति मॉडल में अपना दूसरा पूर्ण दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया 2024 की आजादी के लिए टीमें तैयार करने के लिए 28 जुलाई 2024 को सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली में स्कूल दिवस समारोह. प्रशिक्षण ने प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए स्वयंसेवकों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन किया। कैंप कमांडेंट, डिप्टी कमिश्नर श्री डी.एस. लम्कोटी, की सहायता से शिविर का नेतृत्व किया श्री वी पी माहेश्वरी, सहायक आयुक्त, और श्री. अर्जुन, अपनी टीम के साथ। स्कूल प्रशासन ने प्रशिक्षण के आयोजन के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान किया और सभी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। अन्य जिलों से आये अधिकारी. सहायक आयुक्त श्री अरुण कुमार गुप्ता, श्री एल पी शर्मा, श्री. पी डी वेरखिया, श्री. जे के शर्मा, और श्री. एन के भट्टी उपस्थित थे और उन्होंने अपना समर्थन भी दिया।

फेडरेशन ने किया दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भरने से जिन 3 छात्रों की जान गई इसे लेकर फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग के साथ-साथ आए दिन सदर बाजार में दिल्ली जल बोर्ड व एमसीडी की लापरवाही से बारिशों का अपनी दुकानों के अंदर घुस जाता है और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर सदर बाजार के कुतुब रोड चौक पर दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड व एमसीडी के खिलाफ सैकड़ों व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारी अपने हाथों में बैनर लिए नारे लगा रहे थे। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। साथ ही फेडरेशन के सदस्यों ने मार्केट में पड़े जगह-जगह कूड़े पर झाड़ू लगाकर सफाई की ओर दिखाई की एमसीडी द्वारा इसी प्रकार की कोई सफाई का प्रबंध नहीं किया जा रहा है।

इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा बड़े दुख की बातें जिस प्रकार राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ है वह बड़ा दर्दनाक है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ फिर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ऐसे हादसा अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की लापरवाही सदर बाजार में भी होती रहती है। सीवर लाइन सही से साफ न होने के कारण बारिशों का अपनी दुकानों के अंदर चला जाता है जिसमें शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती रहती हैं और व्यापारियों को लाखों रुपए के माल का नुकसान हो रहा है। लगता है अधिकारी और नेता सदर बाजार में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं तभी वह कार्य करेंगे।

परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने बताया फेडरेशन की ओर से मंत्रियों से लेकर सभी अधिकारियों तक

व्यापारियों की दिक्कतों को लेकर और बारिशों से जलभराव से होने वाले नुकसान व मुश्किलों को लेकर समय-समय पर अवगत कराया गया है। मगर व्यापारियों को मिला क्या हमेशा आश्वासन? अब तो हद हो चुकी है इसीलिए व्यापारियों को अब सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

पम्मा व राकेश यादव ने बताया जगह-जगह जिंदगी के ढेर लगे रहते हैं। सफाई के नाम पर तो व्यापारियों के आंखों में धूल झोंक दी जाती है। जिससे आए दिन हमारे व्यापारी और कर्मचारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और आए दिन इसी कारण सदर बाजार का व्यापार भी काम होता जा रहा है।

चौधरी योगेंद्र सिंह कमल कुमार, व दीपक मित्तल ने कहा करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी सदर बाजार में दिल्ली सरकार, एमसीडी द्वारा सुविधा के नाम की कोई चीज नहीं शौचालय का इतना बुरा हाल है गंदगी सड़कों पर पड़ी रहती है। सदर बाजार थाना रोड पर एमसीडी की मिली भगत से चल रहा है अवैध पार्किंग माफिया रोड़ों के बीचों-बीच गाड़ियां लगा देता है जिसमें जाम बना रहता है। उसके कारण कई बार अपराधी घटनाएं भी होती हैं।

इस अवसर पर पवन खंडेलवाल, चौधरी योगेंद्र सिंह, दीपक मित्तल, सुधीर जैन, राजेन्द्र शर्मा, कमल कुमार, सुरेंदर महेंद्र, कन्हैया लाल, राजकुमार, सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे।

पुलिस की गाड़ी पर फूटा कांवड़ियों का गुस्सा

जमकर मचाया उत्पात; तोड़फोड़ के बाद पलट दी कार

इन दिनों सावन चल रहा है और लोग कांवड़ के साथ बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं कई जगह कांवड़ियों का उत्पात भी नजर आ रहा है। सोमवार को मेरठ रोड पर दुहाई के पास आज सुबह मेरठ से दिल्ली लाइन पर कांवड़ियों के बीच घुसी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार को पलट दिया।

गाजियाबाद। मेरठ रोड पर दुहाई के पास आज सुबह मेरठ से दिल्ली लाइन पर कांवड़ियों के बीच घुसी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। गुस्साए कांवड़ियों ने गाजियाबाद नंबर की पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाए और डंडे मारकर उसके शीशे तोड़ दिए। तोड़फोड़ करने के बाद कांवरिया मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कांवड़ियों की पहचान की जा रही है।

लोनी निवासी अवनीश त्यागी ने गाड़ी पावर कॉरपोरेशन विजिलेंस में किराए पर लगाई हुई है। गाड़ी दुहाई नमो भारत स्टेशन के पास कांवड़िए से टकरा गई थी। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि गाड़ी कांवड़ियों के लिए अधिकृत लेन में घुस गई थी।

पिछले हफ्ते भी हुई थी तोड़फोड़ की घटना

इससे पहले, पिछले हफ्ते गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में रावली रोड के निकट कार की टक्कर लगने से एक कांवड़िए की कांवड़ खंडित हो गई। इस बात से भड़के कांवड़ियों ने कार सवार को बाहर निकालकर पीटा और कार में भी तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं कांवड़ियों ने कार को पलट भी दिया। करीब एक घंटे गुस्साए कावड़ियों ने दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हंगामा किया।

अब गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने पर मिलेंगे 425 रुपये, आदेश जारी

गाजियाबाद जिले के निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लिए अच्छी खबर है। अब गर्भवती के अल्ट्रासाउंड का शुल्क 425 रुपये कर दिया गया है। पहले इसके लिए निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर को 300 रुपये मिलते थे। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों आदेश जारी किया है। इससे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान को गति मिलेगी।

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत पीपीपी मोड पर निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों द्वारा किए जाने वाले गर्भवती के अल्ट्रासाउंड का शुल्क शासन स्तर से बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह शुल्क 300 प्रति गर्भवती थी जो बढ़ाकर 425 रुपये कर दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल इस अभियान से बहुत कम निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले जुड़ रहे थे। वह लगातार शुल्क में वृद्धि के लिए मांग कर रहे थे। इस मांग को जायज मानते हुए शासन स्तर से बढ़ा दिया गया है।

हर महीने लगाया जाता है शिविर

जिले में प्रतिमाह की 1916 और 24 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती की जांच के लिए इस अभियान के तहत विशेष जांच शिविर लगाया जाता है। इस अभियान के तहत हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को भी चिन्हित करते हुए उनकी निगरानी बढ़ाने पर काम किया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जांच मद में पीपीपी मोड पर ई-रूपी वाउचर के माध्यम से किये जा रहे अल्ट्रासाउंड की वर्तमान दर में परिवर्तन किया गया है।यह ई-रूपी वाउचर के माध्यम से पीएमएसएमए दिवसों पर गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड हेतु 300/- प्रति अल्ट्रासाउंड है।

वर्तमान में निर्धारित दर

अल्ट्रासाउंड की उक्त निर्धारित दर को परिवर्तित करते हुए रु0 425/- प्रति अल्ट्रासाउंड की दर कर दिया गया है। उक्त सूचना से सभी सूचीबद्ध निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को अवगत करा दिया गया है। विभाग इसका जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने में जुट गया है, जिससे सूचीबद्ध निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की संख्या में बढोत्तरी की जा सके।

महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि उक्त परिवर्तित दर के अनुसार पीएमएसएमए दिवसों पर समस्त गर्भवती महिलाओं(गर्भावस्था के द्वितीय /तृतीय त्रैमास) के अल्ट्रासाउंड के लिए वित्तीय नियमों का पालन करते हुए रुपये 425/- प्रति अल्ट्रासाउंड की दर से ई-रूपी वाउचर जारी कर, सूचीबद्ध निजी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के माध्यम से अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

नोएडा में 31 जुलाई और 1 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं

नोएडा में कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं 31 और एक अगस्त को भौतिक रूप से संचालित नहीं होंगे। दोनों दिन कक्षाएं वर्चुअल माध्यम से संचालित होंगी। दो अगस्त को जिलाधिकारी पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित कर चुके हैं।

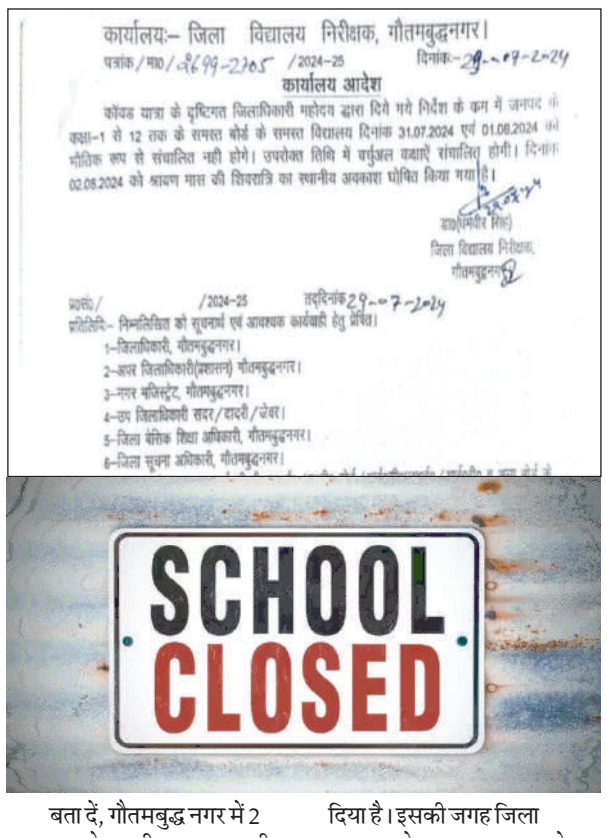

ग्रेटर नोएडा। नोएडा में 12वीं तक के स्कूल 31 जुलाई और 1 अगस्त को बंद रहेंगे और सारी कक्षाएं वर्चुअल लगेंगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वह कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं 31 और एक अगस्त को भौतिक रूप से संचालित नहीं करेंगे। दोनों दिन कक्षाएं वर्चुअल माध्यम से संचालित होंगी। दो अगस्त को जिलाधिकारी पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित कर चुके हैं।

2 अगस्त को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

बता दें, गौतमबुद्ध नगर में 2 अगस्त को स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सावन मास की शिवरात्रि जलाभिषेक के तीन अगस्त के अवकाश को निरस्त कर दिया है। इसकी जगह जिला प्रशासन दो अगस्त शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। दो अगस्त को जिले के सभी स्कूल-कॉलेज के साथ सरकारी कार्यालय में अवकाश रहेगा।

उल्टा पड़ा साइबर ठग का दांव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सामने खुद खा गया गच्चा; चैट वायरल

गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की साइबर ठग के साथ चैट इन दिनों खूब वायरल हो रही है। दरअसल ठग ने इंजीनियर को ठगी का लिंक सेंड किया। इंजीनियर ने उससे कहा कि आपकी यह साइट बिल्कुल फर्जी लग रही है। इसे और बेहतर बनाने के लिए वह उनकी मदद कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें 20 हजार रुपए देने होंगे। इसके लिए वह राजी भी हो गया।

गुरुग्राम। साइबर ठगों द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के मैसेज और फर्जी लिंक भेज कर ठगी करने का तारीक आम हो गया है। लेकिन एक साइबर ठग ने जब गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ठगने के लिए फर्जी लिंक भेजा तो वह तुरंत ही पकड़ा गया।

गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साइबर ठग को उसी की भाषा में उत्तर दिया। उससे कहा कि आपकी यह साइट बिल्कुल फर्जी लग रही है। इसे और बेहतर बनाने के लिए वह उनकी मदद कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें 20 हजार रुपए देने होंगे।

गौरव शरण ने चैट का शेयर किया स्क्रीन शॉट

गुरुग्राम की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव शरण ने अपने एक्स पोस्ट पर साइबर ठग से हुई इस बातचीत का स्क्रीनशॉट साझा किया है। स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि एक साइबर ठग ने मैसेज किया और कहा कि वह एचडीएफसी बैंक का प्रतिनिधि है। उसने बैंक का फर्जी लिंक भेज कर उस पर पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा।

तुरंत ही गौरव इसे समझ गए और उन्होंने मैसेज में लिखा कि यह बिल्कुल फर्जी दिख रहा है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्हें एचडीएफसी की तरह दिखने वाली एक बेहतर वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए 20 हजार रुपए देने होंगे।

कई यूजर्स ने दी अपनी प्रतिक्रिया

इस पर साइबर ठग ने उनसे डेमो देने के लिए भी कहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा इस वार्तालाप का स्क्रीनशॉट एक्स पोस्ट पर साझा करने के बाद यह तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने यहां तक कहा कि धोखेबाज को धोखा मिला।

रेलवे तकनीशियन को हमलावरों ने मारी धड़ाधड़ तीन गोलियां, रास्ते से गुजर रहे युवकों ने पहुंचाया अस्पताल

गाजियाबाद में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। आए दिन लूट-चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार रेलवे तकनीशियन पर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में रेलवे तकनीशियन को तीन गोलियां लगी हैं। उन्हें घायल हालत में रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार युवकों ने अस्पताल पहुंचाया है।

गाजियाबाद। बाइक सवार रेलवे तकनीशियन को अज्ञात हमलावरों ने तीन गोली मारकर घायल कर दिया। पीड़ित को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। चिपियाना के करण एन्क्लेव निवासी 50 वर्षीय राजनारायण यादव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तकनीशियन हैं। शनिवार देर रात वह ट्रेन से स्टेशन उतरकर बाइक से घर जा रहे थे। रात करीब साढ़े 11 बजे एबीईएस अंडरपास से जब वह चिपियाना के लिए मुड़े तभी उन्हें लगा कि उनकी बाइक से फट-फट की आवाज आ रही है।

बाइक रोकते ही सड़क पर गिर गए

कुछ दूर बाइक चलाने के बाद उन्हें बाजू से खून निकलता दिखा और पैर में भी दर्द हो गया। बाइक रोकते हुए वह सड़क पर गिर गए। राजनारायण के भतीजे सुनील यादव के मुताबिक मौके से गुजर रहे दो बाइक सवार युवकों ने उनके चाचा को सड़क पर गिरा देख मदद करते हुए अस्पताल पहुंचाया और उन्हें भी सूचना दी।

सुनहरे कल को निगल गई भ्रष्ट व्यवस्था

डॉ. आशीष वशिष्ठ

हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्र व्यवस्थागत खामियों को गिना रहे हैं। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं 'छात्रों की हत्या बंद करो'... इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

दिल्ली की प्रतिष्ठित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ओल्ड राजेंद्र नगर की इस दर्दनाक हादसे ने देशवासियों को झकझोर दिया। जो युवा आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने संजोकर अपना घर बाहर, सुख सुविधा छोड़कर दिल्ली परीक्षा की तैयारी के लिए गये थे, वो मुनाफाखोर कोचिंग संचालक की धूर्तता, सरकारी अमले की अकर्मण्यता और लापरवाही के चलते अपनी अमूल्य जिंदगी गंवा बैठे।

सोचिये उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। इस व्यवस्था के व्यवस्थापक इतने गैर जिम्मेदार और लज्जाहीन हैं कि उनकी नजर में किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। ये हालात राष्ट्रीय राजधानी के पॉश इलाकों में संचालित कोचिंग सेंटर के हैं, दूसरे शहरों और कस्बों की बात ही क्या की जाए।

इस साल जलभराव की वजह से दिल्ली की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 22 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र की मौत करंट लगने से हो गई। असल में दो चार दिन के शोर गुल और कार्रवाई की नौटंकी के बाद व्यवस्था फिर से पुरानी पटरी पर दौड़ने लगती है। सौ प्रतिशत दावे के साथ कहा जा सकता है कि, राव कोचिंग सेंटर मामले में भी कार्रवाई और सख्ती की पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी।

हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्र व्यवस्थागत खामियों को गिना रहे हैं। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं 'छात्रों की हत्या बंद करो'... इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये हादसा सरकार और कोचिंग संचालकों पर गंभीर सवालों के कटघरे में खड़े करता है।

ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है जब दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। 15 जून 2023 को दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के हब मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल हो गए। जांच में पता चला कि आग बिजली के मीटर में लगी थी, जो देखते-देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटरों में करीब 200-250 छात्र मौजूद थे। छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ीं, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सीढ़ियों का सहारा लिया। कुछ छात्रों ने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी। इसके अलावा 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की दो छतें गिर गईं। इस हादसे में चार छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई वहीं 13 लोग घायल हो गए।

दिल्ली हो या फिर कोई दूसरा शहर कमोबेश सरकारी अमले की कार्यप्रणाली एक समान ही होती है। हादसे के बाद प्रशासनिक अमला गहरी नींद से ऐसे जागता है मानो उन्हें इस बात का इल्म ही न हो कि उनके क्षेत्र या शहर में क्या अनियमितता हो रही हैं। जब कोई दुर्घटना घटती तब पता चलता है कि व्यवस्था में कितनी खामियां और छेद हैं। और इन खामियों और छेदों से छनकर आने वाला लाभ नीचे से ऊपर तक बंटता है। पूर्व की घटनाओं पर गौर किया जाए तो अधिकतर मामलों में दोषी साफ तौर पर बच जाते हैं, या मामूली सजा पाते हैं। हादसा की जिम्मेदारी तो संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की भी होती है, लेकिन ऐसे मामलों में वो अपना पल्ला झाड़कर किनारे खड़े हो जाते हैं।

बीती 14 अप्रैल 2024 को राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा के एक हॉस्टल में आग लगने से 8 स्टूडेंट्स झुलस गए। घटना के वक्त हॉस्टल में 60 से ज्यादा छात्र मौजूद थें आग लगने के बाद हॉस्टल में भगदड़ मच गई इस बीच एक छात्र ने अपनी जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी।जांच में हॉस्टल मालिक की बड़ी लापरवाही सामने आई। हॉस्टल मालिक ने अंदर ही बिजली का एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाया हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ।

लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज में नवल किशोर रोड पर तीन मंजिला स्कॉलर्स फोरम टॉवर है। इसके पहले तल पर स्कॉलर्स फोरम कोचिंग चलता है। यहां छात्र-छात्राएं आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए पढ़ाई करते हैं. दूसरी और तीसरी मंजिल पर हॉस्टल हैं। दूसरी मंजिल के हॉस्टल में 14 कमरों में कुल 28 छात्राएं रह रहीं हैं। 2 जून 2024 की शाम को छात्राएं अपने कमरे में थी। शाम करीब छह बजे तीसरी मंजिल के कमरा नंबर दो की एसी में शॉर्ट सर्किट से धमाका हो गया। इसके बाद तीन मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। सभी कमरों में धुआं फैल गया। करीब 28 छात्राओं में चीख-पुकार मच गई। एक कमरे का शीशा तोड़कर हॉस्टल कर्मियों ने छात्राओं को बाहर निकाला. जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

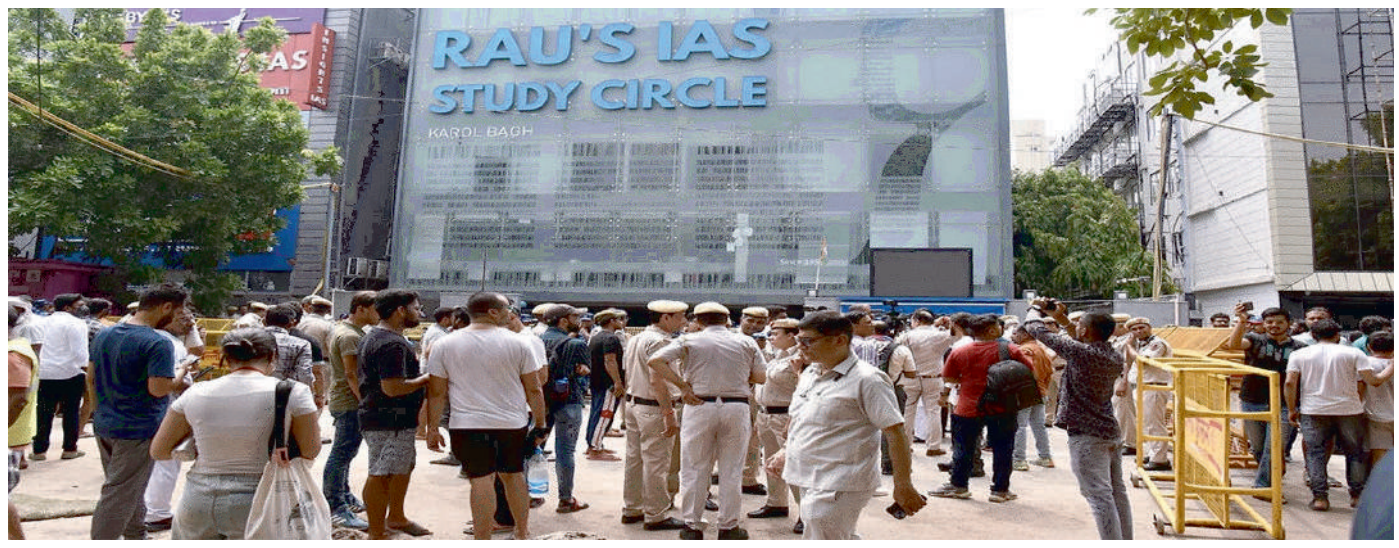

24 मई 2024 को गुजरात के सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में चल रही एक कोचिंग में भीषण आग लगने से 23 छात्रों की मौत हो गई। आग बिल्डिंग में आने जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के पास रखे ट्रांसफॉर्मर में लगी थी। जैसे ही आग लगी अंदर मौजूद छात्र उतरने के लिये नीचे पहुंचे। लेकिन आग की वजह से वह लौटकर चौथी मंजिल पर चले गए, जहां एक फाइबर का शेड था और अंदर जिम के लिए रखी गई रबर की चटाई और टायर के कारण आग ज्यादा फैली, जिससे बच्चे आग की चपेट में आ गई। घटना से हिली सरकार ने पूरे राज्य में वाणिज्यिक भवनों में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया।

31 मई 2024 हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 16 के एससीओ नंबर 195 की प्रथम मंजिल पर बिजली के मीटर बोर्ड में दोपहर लगभग 12 बजे अचानक आग लग गई। आग के कारण काफी धुंआ हो गया और इससे दूसरी मंजिल पर बने हारट्रोन इंस्टीट्यूट में धुआं फैल गया। जिस समय हादसा हुआ, तो हारट्रोन इंस्टीट्यूट में लगभग 25 से 30 विद्यार्थी कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। धुंआ फैलने के कारण विद्यार्थियों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी। इसके बाद स्थानीय दुकानदार ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगाई और ऊपर जाकर फंसे हुए विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए।

ये घटनाएं उन सरकारी दावों-वादों की पोल खोलती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि प्रशासन व्यवसायिक और अन्य गतिविधियों का संचालन नियम कानून के दायरे में करवा रहा है। यह भी अफसोस की बात है कि ऐसे हादसों की जांच तो होती है, लेकिन उनके आधार पर क्या कार्रवाई हुई, यह मुश्किल से ही पता चलता है। लगता है कि हादसों की तरह उनसे संबंधित जांच रपटों को भी भुला दिया जाता है।

सरकार को कोचिंग संचालन के सख्त नियम बनाने चाहिएं। वहीं स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, फायर विभाग और अन्य संबंधित विभागों को व्यावसायिक भवनों के निर्माण और संचालन में कागजी कार्रवाई और फाइलों का पेट भरने की बजाय ईमानदारी और पारदर्शिता से नियम कानून का पालन करवाना चाहिए। यहां सवाल देश के युवाओं और छात्रों का है। यहां सवाल देश के भविष्य का है। यहां सवाल छात्रों के अभिभावकों का है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां देशभर से लाखों छात्र भविष्य बेहतर करने का सपना लेकर तैयारी करने आते हैं। दिल्ली में इस तरह के हादसे होना बेहद चिंता की बात है। इस घटना पर एनडीआरएफ और सरकार अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो 3 जिंदगियां तो वापस आने से रहीं।

- डॉ. आशीष वशिष्ठ

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

पेश कर सकती है होंडा भारत में निर्मित भविष्य की कारों के लिए नया वैश्विक प्लेटफॉर्म

परिवहन विशेष न्यूज

अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रमुख कार निर्माता होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड एक नया वैश्विक प्लेटफॉर्म पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका इस्तेमाल छोटी और मध्यम आकार की कारों में किए जाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार आने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर किया जाएगा और भविष्य में भारत इसका उत्पादन केंद्र बन जाएगा। कुछ रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि कंपनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इस प्लेटफॉर्म को आईसी इंजन और ईवी दोनों के लिए उपयुक्त बनाने की कोशिश कर रही है।

इस प्रयोग का उद्देश्य ब्रांड के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करना और भारत में बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाना है, जो वर्तमान में भारतीय बाजार में गिरावट का सामना कर रहा है। होंडा के पास केवल सिटी, अमेज और एलिवेट जैसे मॉडल उपलब्ध हैं, जो कथित तौर पर उम्मीद के मुताबिक संतोषजनक बिक्री के आंकड़े दे रहे हैं।

2025 के अंत में शुरू होगा टाटा का जेएलआर प्लांट, सितंबर में रखी जाएगी नींव

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) प्लांट के 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में स्थापित होने वाला कारखाना जेएलआर के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा। यह कारखाना रानीपेट जिले के पनपक्कम के पास 400 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा। चेन्नई और एन्नोर बंदरगाहों से लगभग 90 किमी की दूरी होने का भी फायदा होगी मिलेगा।

मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया गया हैं कि कंपनी 9,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट की आधारशिला इस साल सितंबर तक रखने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसकी आधारशिला रख सकते हैं। इसके बाद 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में 12-18 महीनों के भीतर प्लांट चालू होने की उम्मीद है। इसमें जेएलआर की प्रीमियम गाड़ियां असेंबल होने के बजाय पूरी तरह से निर्मित होंगी।

रिपोर्ट के अनुसार अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्लांट में कौन से वाहन बनाए जाएंगे। उम्मीद है कि टाटा ईएमए आर्किटेक्चर पर आधारित टाटा ईवी का उत्पादन करेगा साथ ही निर्यात के लिए जेएलआर से इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (ईएमए) पर आधारित मेड इन इंडिया मॉडल भी बनाएगा।

यह परियोजना चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य आगामी बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से होसकोटे और श्रीपेरंबदूर के बीच संपर्क में सुधार करना है।

चीन में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में उछाल

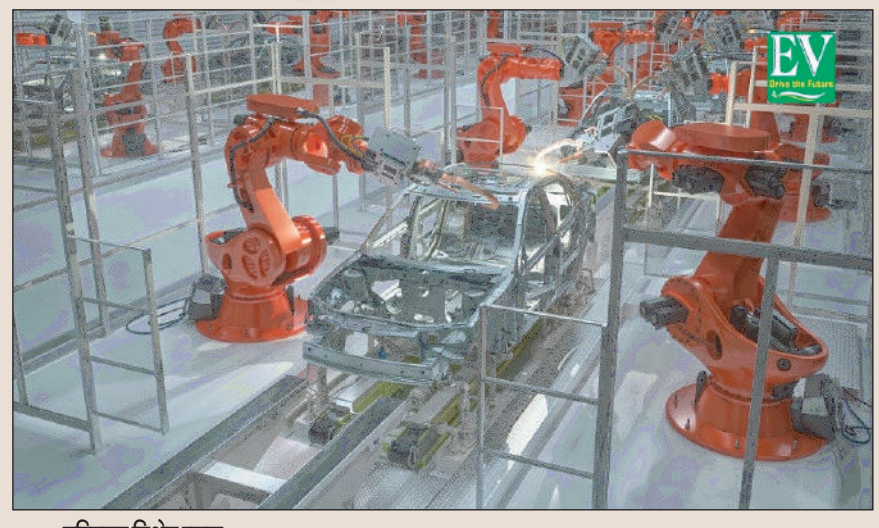

परिवहन विशेष न्यूज

चीन का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग न केवल देश के ऑटोमोटिव परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक भी है और सतत विकास के प्रति चीन की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के चीनी सरकार के प्रयासों ने नवाचार में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा दिया है। इसने तकनीकी उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है, जिससे चीन को इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मिली है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र ने अनेक रोजगार अवसर सृजित किए हैं, रोजगार में योगदान दिया है तथा कुशल कार्यबल को बढ़ावा दिया है। इससे वैश्विक बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हुई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने बैटरी उत्पादन से लेकर आवश्यक सामग्रियों तक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है, जिससे चीन के आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिला है।

चीन की ईवी रणनीति जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफी हद तक कम करती है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। यह बदलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और चीन को जलवायु परिवर्तन शमन में अग्रणी बनाता है।

घरेलू ईवी उद्योग को बढ़ावा देकर, चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रहा है, आयातित तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े भू-राजनीतिक जोखिमों को कम कर रहा है।

चीनी ईवी निर्माता वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं, न केवल वाहनों का बल्कि प्रौद्योगिकी और सेवाओं का भी निर्यात कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नया आकार दे रहा है, जिसमें चीन नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और क्षमता देश को एक टिकाऊ और मजबूत आर्थिक भविष्य की ओर ले जा रही है, जो नवाचार, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है।

मैपमाईइंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक पर डेटा कॉपी करने का आरोप लगाया, कानूनी नोटिस भेजा

परिवहन विशेष न्यूज

मैपमाईइंडिया की मूल कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स ने ओला इलेक्ट्रिक को कथित तौर पर कंपनी का डेटा कॉपी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जबकि भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी ने भारत में अपनी मैपिंग सेवा शुरू की है।

कानूनी नोटिस में मैपमाईइंडिया ने दावा किया कि ओला इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस समझौते का उल्लंघन किया है। 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए नेविगेशन सेवाएँ देने के लिए मैपमाईइंडिया को शामिल किया।

मैपमाईइंडिया के अनुसार ओला को लाइसेंस प्राप्त उत्पाद को किसी अन्य समान प्रतिस्पर्धी उत्पाद के साथ मिश्रित करने, किसी भी रिवर्स इंजीनियरिंग में शामिल होने या लाइसेंस प्राप्त उत्पाद या किसी संबंधित सॉफ्टवेयर के किसी भी एपीआई से स्रोत कोड को निकालने/कॉपी करने का कोई भी प्रयास करने से प्रतिबंधित किया गया है।

मैपमाईइंडिया ने नोटिस में कहा कि ओला मैप्स ने हमारे डेटा को कैश करके सेव कर लिया, जो 2021 में हस्ताक्षरित लाइसेंसिंग समझौते का उल्लंघन है। दिल्ली स्थित फर्म ने यह भी कहा कि वह ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु स्थित फर्म ने गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में ओला मैप्स लॉन्च किया। फर्म ने गूगल मैप्स से हटकर अपने संचालन को इन-हाउस मैपिंग सेवा में स्थानांतरित कर दिया। भाविश अग्रवाल के अनुसार इस उपाय से उनकी कंपनी को हर साल 100 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

ओला मैप्स की मुफ्त पेशकश के जवाब में गूगल ने भी भारत में डेवलपर्स के लिए गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म की कीमत में 70% तक की कटौती की है। टेक दिग्गज ने यह भी कहा कि वह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ काम करने वाले डेवलपर्स को 90% की छूट देगा।

मैपमाईइंडिया को दिसंबर 2021 में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में 106 करोड़ रुपये के परिचालन राजस्व के साथ अपने शुद्ध लाभ में 35% की वृद्धि के साथ 38.2 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

ओला इलेक्ट्रिक 2 अगस्त को शेयर बाजार में उतरने वाली भी है।

ईवी स्कूटर बनाने वाले स्टार्टअप ने जुटाए 167 करोड़

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ने 'सीरीज ए फंडिंग' राउंड में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 167 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। 'सीरीज ए फंडिंग' स्टार्टअप द्वारा पूंजी जुटाने की प्रक्रिया का एक चरण है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस फंडिंग राउंड में मौजूदा और नए निवेशकों ने हिस्सा लिया। सिंपल एनर्जी फिलहाल दो इलेक्ट्रिक वाहन सिंपल वन और सिंपल डॉट वन बेचती है। कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने में करेगी।

सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा, ₹बेंगलुरु में हमारे शुरुआती ग्राहक आधार से हमें जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है, वह वाकई उल्लेखनीय है। हम अपने सभी निवेशकों को हमारे ब्रांड में विश्वास बनाएं रखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।"

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाई इलेक्ट्रिक कार, बीटेक छात्रों ने किया कमाल

परिवहन विशेष न्यूज

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के बीटेक छात्रों ने प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक कार बनाकर कमाल कर दिया। यह जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि छात्रों ने पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कम लागत में इलेक्ट्रिक कार बनाकर इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा और रजिस्ट्रार प्रो. संजीव शर्मा ने प्रोजेक्ट कार का टेस्ट ड्राइव लिया और छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्रकुमार ने बताया कि ईवी कार की कीमत 70 हजार रुपये है। कार के ब्रेक लगाने पर भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से बैटरी चार्ज होती रहती है। भविष्य में छात्र इसे सोलर कार में बदलेंगे। इसका पेटेंट भी कराया जाएगा। ईवी कार प्रोजेक्ट बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र आयुष आनंद, दीपांशु, पुष्पराज आर्य और बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र अनिकेत की कड़ी मेहनत का नतीजा है। विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने इसका निर्देशन किया है और तकनीकी में सुरेश अहलावत का भी सहयोग शामिल रहा। ईवी कार में एंड्रॉयड आधारित डिस्प्ले और एमआईडी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो कार की स्पीड, बैटरी प्रतिशत, चार्जिंग स्टेटस, डोर लॉक-अनलॉक और गियर मोड को प्रदर्शित करता है। इसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर विभाग की लैब में ही विकसित किया गया है। ईवी कार में दो किलोवाट की बीएलडीसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉपस्पीड 42 एच, 60 वी बैटरी के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।

घरेलू बाजार पर दबदबा बनाने के लिए ईवी कंपनी करेगी निर्यात, जल्द ही लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक

परिवहन विशेष न्यूज

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अब निर्यात पर ध्यान दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। देश में बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखने वाली और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचने वाली ओला इलेक्ट्रिक अब निर्यात यानी विदेश में अपने उत्पाद बेचने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा कंपनी अगले महीने यानी अगस्त में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक का नाम भी आ रहा है। हर 15 अगस्त को कंपनी कोई न कोई बड़ी घोषणा करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले 15 अगस्त को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर सकती है।

फिलहाल कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 35 फीसदी है, जिसे वित्त वर्ष 2024 के अंत तक बढ़ाकर 39 फीसदी करने का लक्ष्य है। घरेलू बाजार पर दबदबा बनाने के बाद कंपनी का फोकस अब निर्यात पर है। कंपनी जल्द ही निर्यात शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कंपनी का मुख्य फोकस आरएंडडी और तकनीक पर है। कंपनी ने बताया कि उसके पास 379 पेटेंट हैं।

कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उनका फोकस भारत को ईवी हब बनाने पर है। कंपनी ने कहा कि 2020 में हमने एक बाजार तैयार किया और अब तक हमने 7 प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, इसके साथ ही हमने 4 प्रोडक्ट की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ बाजार है और हमने 2 पहिया वाहनों से इसकी शुरुआत की है।

स्व-निर्देशित शिक्षा के लाभ

विजय गर्ग

स्व-निर्देशित शिक्षा आवश्यक रूप से अलगाव में नहीं की जाती है - इसे अकेले या सहायक शिक्षण वातावरण के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। संदर्भ जो भी हो, मुख्य कारक यह है कि दिशा सीखने वाले द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि किसी बाहरी प्राधिकारी द्वारा।

स्व-निर्देशित शिक्षा केवल शिक्षा के दृष्टिकोण से कहीं अधिक है। इसके बजाय, यह जीवन का एक नया तरीका है। तेजी से, लोग उन लोगों के पारंपरिक मार्गों का अनुसरण करने के बजाय अपने स्वयं के रास्ते बनाने के इच्छुक हैं जो उनसे पहले चले गए थे। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ने के साथ, हर समय नई नौकरियाँ अस्तित्व में आ रही हैं। स्व-निर्देशित शिक्षा जिज्ञासा और सीखने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित उद्यमशीलता संस्कृति की ओर बढ़ने का संकेत देती है। छात्र अधिक ऑनलाइन कक्षाओं और मोबाइल लर्निंग तक पहुंच चाहते हैं, भले ही इसका मतलब घर पर अपने समय में सीखने की खोज करना हो। इसके अलावा, जैसे-जैसे कर्मचारी कार्य/जीवन संतुलन के साथ संघर्ष करते हैं, वे तेजी से छोटे विस्फोटों या तुरंत समाधानों में सीखना चाहते हैं। मोबाइल उपकरणों के विस्फोट और चौबीसों घंटे कनेक्टिविटी के साथ, हम जब भी और जहां भी हों, सीखने के संसाधनों तक पहुंच रखते हैं। चाहिए कि वो। तो इस प्रकार की स्व-निर्देशित शिक्षा कैसे काम करती है, और क्या यह वास्तव में छात्रों और कर्मचारियों को असीमित क्षमता प्रदान कर सकती है? स्व-निर्देशित सीखने की अवधारणा स्व-निर्देशित शिक्षा पहल के बारे में है। एक स्व-निर्देशित शिक्षार्थी के रूप में, आप अपनी स्वयं की सीखने की ज़रूरतों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने, सही संसाधन खोजने और अपनी प्रगति की निगरानी करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। यह अवधारणा एक निर्धारित पाठ्यक्रम से केवल एक या दो पाठ्यक्रम चुनने की तुलना में कहीं अधिक लचीली है, जैसा कि हम स्कूल में करने के आदी हैं। स्व-निर्देशित शिक्षा आवश्यक रूप से अलगाव में नहीं की जाती है - इसे अकेले या सहायक शिक्षण वातावरण के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। संदर्भ जो भी हो, मुख्य कारक यह है कि दिशा सीखने वाले द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि किसी बाहरी प्राधिकारी द्वारा। स्व-निर्देशित शिक्षा के लाभों का समर्थन करने के लिए मजबूत शोध मौजूद है। यदि हमें कम उम्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, तो यह हमारे आत्मविश्वास के साथ-साथ परियोजनाओं के साथ बने रहने और हमारी पहल का उपयोग करने की हमारी क्षमता का निर्माण करता है। हम उन विषयों के बारे में अपने ज्ञान में सुधार करके स्वाभाविक रूप से संतुष्टि प्राप्त करते हैं जिनका हम वास्तव में आनंद लेते हैं। नियमित स्कूली शिक्षा के साथ समस्या यह है कि इसमें 'पारंपरिक' विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है, जो कोडिंग से लेकर बढ़ईगीरी तक किसी व्यक्ति की रुचियों की लगातार बढ़ती सीमा को ध्यान में रखने में विफल होती है। उभरती हुई स्व-निर्देशित शिक्षण पद्धतियाँ स्वतंत्र शिक्षा में सफल होने के लिए, आपके पास सही दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए न केवल अत्यधिक आत्म-अनुशासन और संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता है, बल्कि आपको अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में सक्षम और इच्छुक भी होना चाहिए। यह कौशल सेट केवल एक परीक्षण के लिए तथ्यों को याद रखने से कहीं आगे जाता है। स्व-निर्देशित शिक्षण विधियों में पारंपरिक रूप से अनुसंधान और समूह कार्य शामिल हो सकते हैं। आज के हाइपर-कनेक्टेड समाज में भी, बुनियादी बातों पर वापस लौटने और वास्तव में किताब पढ़ने और अन्य लोगों से बात करने के लिए समय निकालने की अभी भी जगह है। लेकिन यह हर किसी के लिए काम नहीं करता है, और अध्ययनों से पता चलता है कि हममें से जो लोग स्मार्टफोन के साथ बड़े हो रहे हैं, उनका ध्यान केंद्रित करने का समय बहुत कम हो रहा है। दूसरा पहलू यह है कि एक साथ कई काम करने की हमारी क्षमता में सुधार हुआ है। दूसरी स्पष्ट विधि ऑनलाइन स्व-निर्देशित शिक्षा है - और इसके बारे में जाने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। अधिकांश समय इसके लिए वित्तीय निवेश की भी आवश्यकता नहीं होती है। लिंकडइन लर्निंग और कौरसेरा जैसी समर्पित साइटों से लेकर यूट्यूब जैसे वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म तक, आपको ऐसे विषय को खोजने में कठिनाई होगी जो कहीं शामिल नहीं है। आज के छात्र उन विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच के भूखे हैं जिन्हें वे कवर नहीं कर पाते हैंमानक पाठ्यक्रम के तहत, चाहे वह डिजिटल चित्रण हो, ई-कॉमर्स, या एआई। कॉलेज स्तर पर, कुछ लोग अपने कौशल को आकर्षक पक्ष के साथ आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर बनाना या वर्चुअल फ्रीलांसर बनना। यह निश्चित है कि ऑनलाइन स्व-निर्देशित

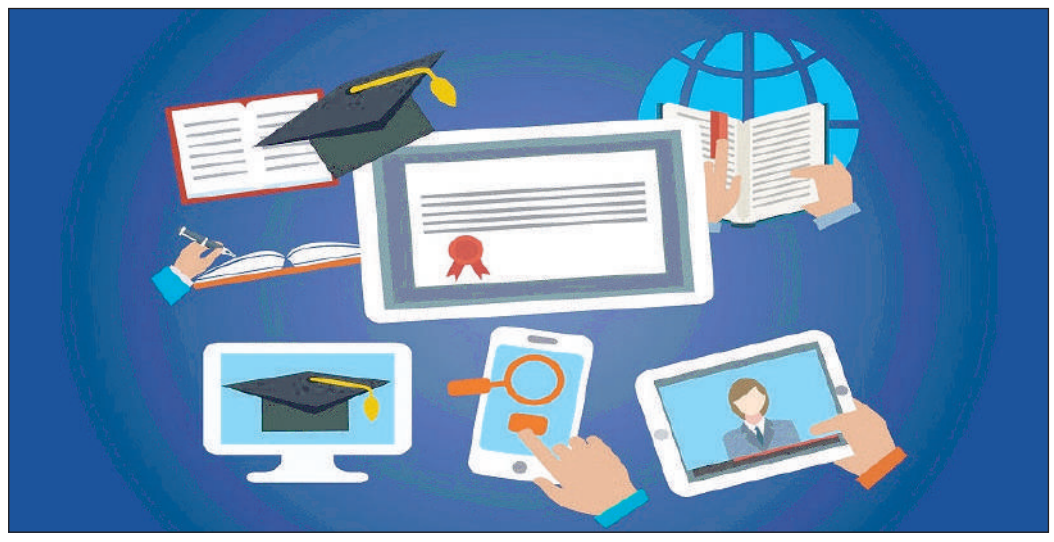

शिक्षा के लिए बहुत बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है, और यह न केवल शिक्षा जगत से संबंधित है, बल्कि कार्यस्थल से भी संबंधित है। स्व-निर्देशित शिक्षा के पक्ष और विपक्ष तो स्व-निर्देशित सीखने के क्या लाभ हैं? सबसे पहले, सबसे संतोषजनक लाभों में से एक यह है कि आप यह चुन सकते हैं कि आप क्या (और कैसे) सीखते हैं। यह आपको अपनी व्यक्तिगत सीखने की शैली को जानने में मदद करता है, चाहे वह पढ़ना, देखना, करना आदि हो। और सच्ची रुचियों को आगे बढ़ाने से वास्तविक आनंद मिलता है, जिससे आप अपनी शर्तों पर सीखने का आनंद ले सकते हैं। स्व-निर्देशित सीखने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन और मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है। दबाव में सीखना बनाम आनंद के लिए सीखना दो बहुत अलग अनुभव हैं। परिणामों से प्रेरित होने के बजाय, आप अपनी जिज्ञासा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अपने आप में बहुत सशक्त करने वाला है. बेशक, सीखने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने से जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं। स्व-निर्देशित शिक्षा के लिए अभी भी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, चाहे आप इसे जिस भी तरीके से देखें। हममें से कई लोग यह मानकर खुद से सीखना बंद कर देते हैं कि हम पर्याप्त रूप से स्मार्ट या आत्म-प्रेरित नहीं हैं। लेकिन यह नकारात्मक मानसिकता ही हमें पीछे खींचती है। डिजिटल युग के लिए स्व-निर्देशित शिक्षा डिजिटल युग में, ऑनलाइन सीखने के लिए नए उपकरणों, तकनीकों और प्रतिमानों के साथ कथित कमियों को कम किया जा सकता है। खोज इंजनों पर निर्भरता के समय में, हम पहले से ही अपने सीखने में अधिक से अधिक आत्म-निर्देशित होते जा रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। स्व-निर्देशित सीखने के फायदे और नुकसान संगठन के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। कार्यस्थल में कुछ भूमिकाएँ स्वायत्त सीखने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, जबकि अन्य को अधिक सहयोग और सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अधिकांश को दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। कंपनियाँ कर्मचारियों को ऑनलाइन टूल तक पहुँच प्रदान करते हुए सीखने की प्रक्रिया का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत रूप से छोड़ना चाह सकती हैं जो वास्तविक समय में सहयोग और सलाह प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। स्व-निर्देशित शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसकी भूमिका को व्यक्ति और समग्र रूप से कंपनी की ज़रूरतों के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी के महान लाभों में से एक यह है कि यह हमें रैखिक, पाठ-आधारित शिक्षा से परे ले जाती है, हममें से उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो अन्य तरीकों से सबसे अच्छा सीखते हैं - और जिन्होंने शायद इस बिंदु तक खुद को प्रेरित करने के लिए संघर्ष किया है। चूँकि इनमें से कई शिक्षण प्रौद्योगिकियाँ इंटरैक्टिव हैं, इसलिए ऐसा वातावरण बनाना बहुत आसान है जहाँ सीखना मज़ेदार हो, ई-पुस्तकें, शिक्षण ऐप्स, युटुब, विकिपीडिया, गेमिफ़िकेशन और शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज़ का अधिकतम लाभ उठाना। शोध से पता चलता है कि डिजिटल शिक्षण विधियों का उपयोग करने वाली कक्षाओं में छात्रों ने उच्च प्रेरणा दिखाई - अक्सर कक्षा में जल्दी आ जाते हैं। इसके अलावा, ये प्रौद्योगिकियाँ अत्यधिक सुलभ हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कुछ कैसे करना है, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं और इस चुने हुए कौशल को विकसित करने में मदद के लिए वेब-आधारित कक्षाएं, समूह और पाठ ढूंढ सकते हैं - अक्सर मुफ्त में। डिजिटल मूल निवासियों के लिए, सीखने की यह शैली आदर्श है। समय, उपकरण और सही वातावरण के साथ, हम उत्सुकता से विषयों का आनंदपूर्वक अन्वेषण करेंगे, चाहे हमारा रुझान विशेषज्ञ की ओर अधिक हो या सामान्यज्ञ की ओर। और क्या, हम तुम्हें ख़त्म करते हैंपी ऐसे समाज के साथ जहां कौशल सेट अनिवार्य रूप से अधिक विविध हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया हमारी उंगलियों पर है - तो हम सभी अपनी असीमित क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? एक सफल स्व-निर्देशित शिक्षार्थी कैसे बनें हममें से प्रत्येक के पास कुछ न कुछ है जिसे हम सीखना चाहते हैं या उसमें बेहतर होना चाहते हैं, चाहे वह संगीत, भाषाएँ, खाना बनाना, खेल या शिल्प हो। फिर भी हममें से कई लोगों के लिए, ये चीजें जिन्हें हम आज़माना पसंद करते हैं, वे कभी भी हमारी कार्य सूची में शामिल नहीं होती हैं। क्योंकि स्व-निर्देशित सीखने को एक आदत बनाने के लिए सही प्रणाली के बिना, जीवन किसी तरह अपरिवर्तित चलता रहता है। इसलिए, नवोदित उद्यमियों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा को अपनाने का समय आ गया है। अपने जीवन में स्व-निर्देशित शिक्षा को शामिल करने में आपकी सहायता के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं: 1. एक समय में एक विषय चुनें और उस पर अपना पूरा ध्यान दें 2. ऐसे विषय चुनें जिनमें वास्तव में आपकी रुचि हो 3. अपने लक्ष्यों के प्रति विशिष्ट रहें. 'गिटार बजाना सीखो' के बजाय, 'बजाना सीखो' का प्रयास करें 4. प्रत्येक पाठ या कार्य को पूरा करने की एक समय सीमा दें 5. अपने कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में बाँट लें 6. सबसे कठिन कार्यों को टालने के बजाय पहले निपटा लें 7. आवश्यकतानुसार अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन और परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें हमारे पास सीखने के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, यह बात स्पष्ट है। इस प्रकार आपको यह पहचानना भी सीखना होगा कि कोई चीज़ कब उपयोगी या मूल्यवान शिक्षण संसाधन है और कब नहीं। कठोर ऑनलाइन पाठ्यक्रम वेबसाइटों में आमतौर पर उच्च मानक होते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए युटुब पर, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है। अंततः आप शैक्षणिक गेहूं को भूसी से अलग करने में माहिर हो जायेंगे। ₹यदि माता-पिता अपने बच्चों को कोई उपहार देना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते हैं वह है अपने बच्चों को चुनौतियों से प्यार करना, गलतियों से चिंतित होना, प्रयास का आनंद लेना और सीखते रहना सिखाएं₹। जो संगठन ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो सीखने की निरंतरता को बढ़ावा दे, हमें कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार रहना होगा - थोपी गई शिक्षा के माध्यम से नहीं, बल्कि स्व-निर्देशित सीखने के लिए सही वातावरण और संसाधन प्रदान करके। कई लोगों का मानना है कि जैसे-जैसे समाज तेजी से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन से गुजर रहा है, स्व-निर्देशित शिक्षा अंततः भविष्य की शिक्षा के लिए मानक मॉडल बन जाएगी।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

ज्ञान

पढ़ने-लिखने की शैली बदलने का प्रयास करें विजय गर्ग

कई छात्र अक्सर शिकायत करते हैं कि अगर वे दिन में 10-11 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। हम जो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। वहीं कुछ छात्र 7-8 घंटे या उससे कम पढ़ाई करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आप भी इन शिकायत करने वाले छात्रों में से हैं तो आपको अपने पढ़ने-लिखने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। जब आप किसी पाठ को अच्छे से पढ़ने के बाद यह समझने लगते हैं कि अब उससे पूछा जाने वाला प्रश्न आप ही हैंअगर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं तो इस काम को बाद के लिए न छोड़ें। उसी दिन, कंप्यूटर पर संपूर्ण पाठ की अपनी प्रतिलिपि या पावरपॉइंट प्रस्तुति बनाएं। इस काम में आप परिवार के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। फिर दो-चार दिन बाद इन्हें दोहराएं और इसे करने की अपनी क्षमता का विस्तार से आकलन करें। इस तरह आप पाठ को सही तरीके से याद कर पाएंगे। एक ही विषय पर अलग-अलग किताबें पढ़ें किसी विषय पर मजबूत पकड़ बनाने और उसे अच्छे से समझने के लिए उस विषय की किताबें ही पढ़नी चाहिएइतना पर्याप्त नहीं है बल्कि उस विषय के अलावा अन्य किताबें भी पढ़नी चाहिए। गूगल पर संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर अपना नोट्स बनाएं। अलग-अलग जगहों से पढ़ने पर विषय की सही जानकारी मिलती है और अभ्यास भी होता रहता है। इससे विषय पर आपकी पकड़ भी मजबूत होती है. आपके नोट्स भी दूसरे विद्यार्थियों से अलग हो जाते हैं. इस तरह परीक्षक की नजर में आप अन्य छात्रों से अलग दिखेंगे और आपको अधिक अंक मिलेंगे। पढ़ने-लिखने के कई फायदे हैं कभी-कभी हम चीजें पढ़ते हैंबाद में हमें लगता है कि हम भूल गए लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ पढ़कर चीजों को लंबे समय तक याद रखना संभव नहीं है। बेहतर होगा कि आपने जो पढ़ा है उसे एक-दो दिन बाद अपनी कॉपी में अपनी भाषा में लिखने की आदत डाल लें। इसके तीन फायदे हैं. सबसे पहले विषय का अभ्यास किया जाता है। दूसरा यह कि आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, जो किताबी भाषा से अलग होते हैं और तीसरा यह कि आप पढ़ते समय विषय को याद करने की जगह के रूप में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको उसे लिखना होता है। एक पॉकेट डायरी रखें कइस समय जब आप पढ़ाई के बाद या उससे पहले स्कूल-कॉलेज या कहीं और जाते हैं तो आपके दिमाग में विषय से जुड़ी कोई न कोई नई जानकारी आती है या अखबार-पत्रिका देखकर, दूसरों की बातें सुनकर जानकारी मिलती है। इन बातों को तुरंत अपनी पॉकेट डायरी में नोट करने की आदत डालें। यह तरीका बहुत उपयोगी साबित होता है। विधि की जानकारी बार-बार उपलब्ध नहीं होती है। पढ़ाई में कौशल का प्रयोग करें यदि आपमें कुछ रचनात्मक करने की क्षमता है और आप अक्सर अपनी पेंसिल आदि से चित्र बनाते रहते हैंइसलिए अपनी इस कला का उपयोग पढ़ाई-लिखाई में करें। आप दिन भर में जो पढ़ते हैं, शाम को उसकी एक कॉमिक स्ट्रिप बनाएं। इस तरह अभ्यास के साथ-साथ आप पावर प्वाइंट का उपयोग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टिकी नोट्स आसान होंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है. किसी के लिए इतिहास में लिखी कोई महत्वपूर्ण तारीख याद रखना मुश्किल हो जाता है तो किसी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के फॉर्मूले याद रखना परेशान करने वाला होता है। इस तरह की चीज़ेंस्टिकी नोट्स बनाएं और उन्हें अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दें। कभी-कभी उन्हें देखने से याद रखना आसान हो जाएगा।

विवेक और साहस से परिपूर्ण नया बजट

डा. जयंतीलाल भंडारी

निश्चित रूप से वित्तमंत्री सीतारमण ने 7 फीसदी से अधिक विकास दर का लक्ष्य रखते हुए तथा राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 4.9 फीसदी तक सीमित रखते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील करने, रोजगार अवसरों को बढ़ाने तथा विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों से सजा-धजा वर्ष 2024-25 का अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करें कि वर्ष 2024-25 के बजट के विभिन्न प्रावधानों के कारगर क्रियान्वयन से भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा'

यकीनन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 जुलाई को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट की तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यह बजट विवेक और साहस से परिपूर्ण बजट है। यह बजट विकसित भारत के सपने को मजबूती देने वाला बजट है। अमृतकाल के इस ऐतिहासिक बजट में 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखते हुए विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। बजट के इन नवरंगों में कृषि उत्पादकता, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण विकास एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा तथा अनुसंधान व नवाचार एवं अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। जहां वित्तमंत्री सीतारमण ने उद्योग-कारोबार, श्रम, कृषि, एमएसएमई, टैक्सेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, आधारभूत ढांचा, वित्त क्षेत्र सहित बजट से संबंधित विभिन्न पक्षों के लिए अभूतपूर्व आवंटन किए हैं तथा महंगाई नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए हैं, वहीं राजस्व घाटा 1.8 फीसदी तथा राजकोषीय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी तक सीमित रखने में सुझबूझ व चतुराई दिखाई है। खास बात यह भी है कि नए बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए हैं, जो कि जीडीपी का 3.4 फीसदी है। इस पूंजीगत व्यय से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। वस्तुतः यह बजट नई गठबंधन सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज है। वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए जहां वित्तमंत्री की एक मुट्ठी आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सौगातों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दी, वहीं उनकी दूसरी मुट्ठी आर्थिक सुधारों और नए दौर की वैश्विक जरूरतों से संबंधी प्रावधानों के लिए खुलते हुए दिखाई दी।

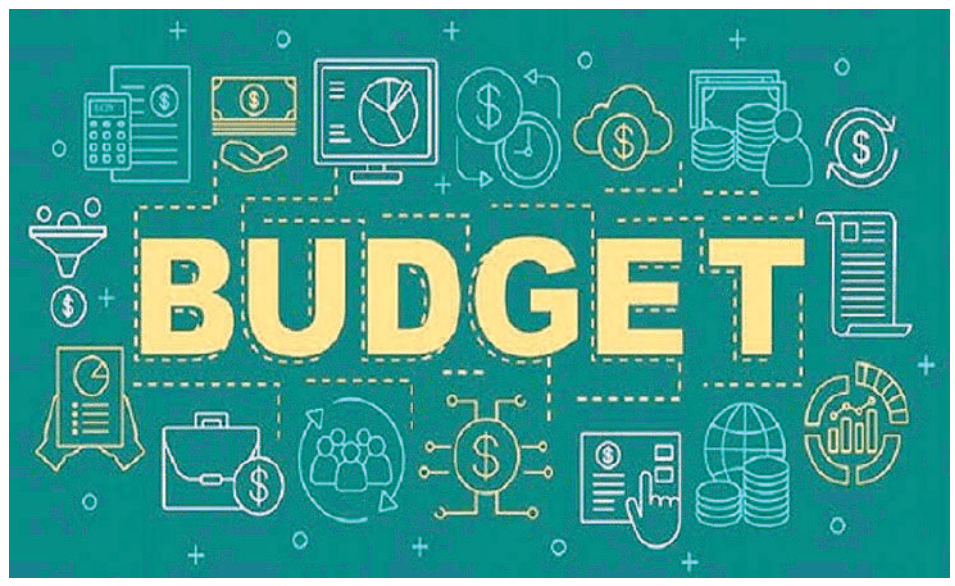

इसमें कोई दोमत नहीं है कि वित्तमंत्री ने नए बजट को बहुआयामी गरीबी में कमी, महिलाओं और युवाओं के विकास, रोजगार वृद्धि, कृषि और किसान हितों, बुनियादी ढांचे की मजबूती, उद्योग-कारोबार की गतिशीलता, रोजगार के नए अवसर, महंगाई पर नियंत्रण, नई मांग का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल शिक्षा, ग्रीन एनर्जी पर खर्च बढ़ाने के बेहतर प्रावधानों से सजाया है। निश्चित रूप से वित्तमंत्री ने आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान किए हैं। नए बजट में 22 जुलाई को पेश आर्थिक समीक्षा के तहत बताई गई हर साल 80 लाख नौकरियों की दरकार के मद्देनजर निजी क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के तहत नई नौकरियों और कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित की है। ऐसी नौकरियों के लिए उत्पादन प्रोत्साहन संबद्ध (पीएलआई), मित्र टैक्सटाइल योजना, मुद्रा योजना, केयर इकोनॉमी क्षेत्रों की पहचान की गई है। वित्तमंत्री ने 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल व अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एक करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्येक छात्र को 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत रोजगार के लिए ऋण की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। एक लाख ऐसे छात्रों को उनके अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा, जो अन्य कोई शासकीय सहायता का लाभ नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से वित्तमंत्री सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के लिए अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए हैं। वित्तमंत्री ने इस बजट के माध्यम से कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए हैं। नए बजट के तहत सरकार कृषि और ग्रामीण विकास पर प्रभावी खर्च बढ़ाते हुए दिखाई दी है। कृषि की विकास दर बढ़ाने, कृषि क्षेत्र की योजनाओं को तर्कसंगत बनाने और कृषि सुधारों को व्यापक प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं। कृषि के बुनियादी ढांचे और कृषि के मशीनीकरण की दिशा में संरचनात्मक सुधार लाने के प्रभावी कदम भी नए बजट में हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले निशुल्क अनाज के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। नए बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को जिला और राज्य कृषि योजनाओं के विकास हेतु आवंटन बढ़ा है। पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कृषि शोध पर आवंटन बढ़ाया गया है। नए बजट के तहत प्राकृतिक खेती पर भारी प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं और आगामी दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मौसम की मार के कारण खराब होने वाली फसलों के लिए समर्थन राशि बढ़ाई जाने से कृषि को नया प्रोत्साहन मिलेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, सरकार ने उनकी भी सहायता बढ़ाई है। निःसंदेह नए बजट के तहत एक लाख करोड़ रुपए के शोध कोष से निजी क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2024-25 के बजट से निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि, बाजारों में उपभोक्ता मांग में तेजी, विनिर्माण और सर्विस क्षेत्र में बड़ा सुधार दिखाई देगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहनमूलक राहत दी गई है। एमएसएमई इकाइयों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत टर्म लोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

वित्तमंत्री सीतारमण ने जहां आयकर की पुरानी रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है, वहीं नई रिजीम के तहत करदाताओं को राहतों से लाभान्वित किया है। नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की कमाई कर मुक्त है। 3 से 7 लाख पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी, 15 लाख से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) सीमा को 50000 रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया गया है। इससे करीब 4 करोड़ वेतनभोगियों व पेंशनभोगियों को लाभ होगा। निश्चित रूप से वित्तमंत्री सीतारमण ने 7 फीसदी से अधिक विकास दर का लक्ष्य रखते हुए तथा राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 4.9 फीसदी तक सीमित रखते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील करने, रोजगार अवसरों को बढ़ाने तथा विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों से सजा-धजा वर्ष 2024-25 का अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करें कि वर्ष 2024-25 के बजट के विभिन्न प्रावधानों के कारगर क्रियान्वयन से भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनने के सपने को साकार करने की डगर पर भी आगे बढ़ा जा सकेगा। अब सरकार को क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा।

युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं

विजय गर्ग

युवाओं को राष्ट्रीय पूंजी के रूप में सराहा जाता है। ये बात भी सौ फीसदी सच है. किसी भी देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। लेनिन ने कहा था कि हम किसी राष्ट्र का भविष्य उसके वर्तमान समय के गीतों से जान सकते हैं। वर्तमान युग में गीतों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जा रहा है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश का भविष्य अच्छा नहीं है। जब हम समाचारों में देखते और सुनते हैं कि किसी नशेड़ी ने अपने माता या पिता की हत्या कर दी, लूटपाट कर ली या नशेड़ी की कहीं मृत्यु हो गई ₹यदि पाया जाता है तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा समाज बीमार हो गया है। इस बीमारी का शिकार सिर्फ युवा लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी होती हैं। जब हम समाज में इतनी बुरी स्थिति देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि देश के युवाओं ने जहां चुना है, उसका दोषी कौन है? देश के नेता आए दिन ऐसी स्थिति पर चिंता जताते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण स्पष्ट है कि हम प्रकृति से टूटकर कॉरपोरेट से जुड़ गये हैं। हमें इंसानों से ज्यादा पैसों की जरूरत हैवे परवाह करते हैं, जैसे सरकारें वोटों की परवाह करती हैं। आज आप बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं उसमें मिलावट, नकली सामान आम बात है। जब हम इन समस्याओं के कारणों पर नजर डालते हैं तो कई अन्य कारणों के साथ-साथ बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में युवा विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं. जो नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, वे अपना हाथ कहीं और मोड़ लेते हैं। बार-बार प्रयास करने पर भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे हताशा में नशे की ओर रुख करते हैं। ये दवाएं बहुत हैंउनके पीछे दुर्भावनापूर्ण राजनीति आसानी से पाई जाती है। नशे की दलदल में फंसे युवा अपने परिवार के साथ-साथ देश का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं के निराशा की खाई में गिरने का कारण देश की बिगड़ती परीक्षा प्रणाली भी है। हाल के दिनों में 2364 ईटीटी शिक्षकों, 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती में देरी, एनईईटी यूजी और यूजीसी नेट के पेपर लीक होने और कई अन्य भर्तियों और पेपरों में भ्रष्टाचार का पता चलने से मेहनतकश युवाओं का मनोबल टूट रहा है।. कबअगर उनकी मेहनत की कोई कीमत न हो तो वे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर हो जाते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

तूफानी रफ्तार से बढ़ रही डिजिटल इकोनॉमी, अगले दो साल में हो जाएगी डबल

आरबीआई का कहना है कि प्रमुख एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए खुदरा भुगतान अनुभव में क्रांति ला दी है। इससे लेन-देन तेज और अधिक सुविधाजनक हो गया है। डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में आरबीआई ई-रूपी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के पायलट परीक्षण के साथ सबसे आगे है। आरबीआई 90 सालों की यात्रा के बारे में बताने के लिए वेब सीरीज लाने की योजना भी बना रहा है।

मुंबई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20 प्रतिशत हो जाएगी। अभी यह जीडीपी का 10 प्रतिशत है। गवर्नर ने 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त (आरबीएफ) पर रिपोर्ट की प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण से अगली पीढ़ी की बैंकिंग का रास्ता खुल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी नवाचार वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल और एकीकृत बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। देश ने न केवल डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) को अपनाया है, बल्कि बायोमीट्रिक पहचान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लाकर और सहमति के आधार डाटा भी साझा कर रहे हैं।

2023 में भारत में इंटरनेट की पहुंच 55 प्रतिशत थी, लेकिन हाल के तीन वर्षों में इंटरनेट यूजर की संख्या में 19.9 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत में प्रति गीगाबाइट (जीबी) डेटा की कीमत दुनियाभर में सबसे कम है। यह औसतन 13.32 रुपये प्रति जीबी है।

यूपीआई ने खुदरा भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी

रिपोर्ट की प्रस्तावना में आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि प्रमुख एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) ने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए खुदरा भुगतान अनुभव में क्रांति ला दी है। इससे लेन-देन तेज और अधिक सुविधाजनक हो गया है। डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में आरबीआइ ई-रूपी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के पायलट परीक्षण के साथ सबसे आगे है। डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, डिजिटल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क और सुविधाजनक कर्ज के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच जैस पहलों के साथ मजबूत हो रहा है।

4500 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोने का भाव भी 950 रुपये घटा

परिवहन विशेष न्यूज

बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद से सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को दिल्ली में चांदी के मूल्य में 4500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। अब इसका मूल्य 84500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं सोने की कीमत में 950 रुपये की कमी देखने को मिली है।

नई दिल्ली। सीमा शुल्क में कटौती के बाद सोना और चांदी के मूल्य में गिरावट का दौर जारी है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में चांदी के मूल्य में 4,500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। अब इसका मूल्य 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यह 2024 में चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट है।

इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 89,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एसोसिएशन का कहना है कि सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक मांग में कमी के कारण चांदी के मूल्य में यह गिरावट रही है।

एसोसिएशन के अनुसार, ज्वेलर्स की ओर से मांग कमजोर रहने के कारण 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के मूल्य में 950 रुपये की कमी हुई और यह 71,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का मूल्य 1,650 रुपये घटकर 70,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुद्धता के इन दोनों मानकों को 24 कैरेट भी कहा जाता है।

कारोबारियों का कहना है कि सोने के मूल्य में कमी का प्रमुख कारण ज्वेलर्स के साथ-साथ खुदरा खरीदारों की ओर से मांग में कमी रहना रहा है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सप्ताह बजट में सोना और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद 23 जुलाई को सोने के मूल्य में 3,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के मूल्य में 3,500 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट हुई थी। तब से अब तक सोने में 5,900 और चांदी में 11,500 रुपये की गिरावट हो चुकी है।

फेडरल बैंक की बैठक पर रहेगी नजर

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी का कहना है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को महंगाई से लड़ाई में सफलता मिल रही है। इससे सितंबर में अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है।

फेडरल रिजर्व की बैठक मंगलवार को शुरू होगी और इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी बुधवार को सामने आएगी। अब निवेशकों की नजर इस बैठक के फैसलों पर रहेगी। अगस्त में आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी होगी। यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो आरबीआई की ओर से भी जल्द कटौती की उम्मीद बढ़ जाएगी।

डीजल में एथनॉल मिलाने का प्रस्ताव नहीं, यह अभी केवल प्रायोगिक स्तर पर- हरदीप पुरी

परिवहन विशेष न्यूज

पुरी से पूछा गया था कि क्या सरकार डीजल में एथनॉल मिलाने को अनिवार्य करने की योजना बना रही है और यदि ऐसा है तो डीजल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिलाने का प्रस्ताव है। पुरी ने उच्च सदन को बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और चुनिंदा ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर डीजल में सात प्रतिशत तक एथनॉल मिलाने का परीक्षण किया है।

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को संसद में बताया कि फिलहाल डीजल में एथनॉल मिलाने को अनिवार्य करने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कहा, डीजल में एथनॉल मिलाने का मुद्दा अभी प्रायोगिक स्तर पर है और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि फिलहाल इसे अनिवार्य करने की कोई योजना नहीं है।'

दरअसल, पुरी से पूछा गया था कि क्या सरकार डीजल में एथनॉल मिलाने को अनिवार्य करने की योजना बना रही है, और यदि ऐसा है तो डीजल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिलाने का प्रस्ताव है। पुरी ने उच्च सदन को बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और चुनिंदा ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर डीजल में सात प्रतिशत तक एथनॉल मिलाने का परीक्षण किया है।

फर्जी आइटीसी दावों की संख्या 51 प्रतिशत बढ़ी

2023-24 में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) दावों की संख्या 51 प्रतिशत बढ़कर 36,374 करोड़ रुपये हो गई। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2022-23 के दौरान, 7,231 मामलों में 24,140 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का पता चला था। इसमें 152 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और

2,484 करोड़ रुपये का कर स्वेच्छा से जमा किया गया।

2023-24 के दौरान, केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा 9,190 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 36,374 करोड़ रुपये का फर्जी आइटीसी शामिल था। इसमें 182 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3,413 करोड़ रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा किए गए।

185 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा सरकार का कर्ज

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि मौजूदा विनिमय दर और अन्य देनदारियों के चलते सरकार का कर्ज चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 185 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 56.8 प्रतिशत हो जाएगा। मार्च, 2024 के अंत में कुल कर्ज 171.78 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 58.2 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी 2023-24 में पहले ही 3.57 ट्रिलियन डालर तक पहुंच चुकी है।

पूरी जांच-परख के बाद ही बैंक खातों को किया जाए कुर्क- सीबीआईसी

कहा गया है कि कर अधिकारी को कुर्की करने से पहले अपराध की प्रकृति शामिल राजस्व की राशि या तस्करी किए गए सामान के मूल्य की जांच सहित सभी जरूरी तथ्यों पर विचार करना चाहिए और इसे फाइल में दर्ज करना चाहिए। जांच में यह बात भी शामिल हो कि अगर खाते को अस्थायी तौर पर कुर्क नहीं किया गया तो खाताधारक बैंकखाते के धन का उपयोग कर सकता है।

दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कहा है कि सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों में बैंक खातों को कुर्क करने की शक्ति का प्रयोग तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच-परख करने के बाद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय इकाइयों को दिए गए निर्देश में सीबीआइसी ने कहा कि जिन मामलों में बैंक खाते कुर्क किए गए हैं, उनमें जांच और निर्णय जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त उन मामलों में छह महीने तक के लिए बैंक खातों को कुर्क करने के बारे में लिखित रूप से आदेश दे सकते हैं, जहां यह राजस्व के हित में या तस्करी को रोकने के लिए हो। ऐसी कुर्की को छह महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

निर्देश में कहा गया है कि कर अधिकारी को कुर्की करने से पहले अपराध की प्रकृति, शामिल राजस्व की राशि या तस्करी किए गए सामान के मूल्य की जांच सहित सभी जरूरी तथ्यों पर विचार करना चाहिए और इसे फाइल में दर्ज करना चाहिए। जांच में यह बात भी शामिल होनी चाहिए कि अगर खाते को कुर्क अस्थायी तौर पर कुर्क नहीं किया गया तो खाताधारक बैंक खाते के धन का उपयोग कर सकता है।

सीबीआइसी ने 22 जुलाई को दिए निर्देश में कहा, चूंकि बैंक खाते की अस्थायी कुर्की राजस्व के हितों की रक्षा के लिए की जाती है और इससे उस व्यक्ति के व्यवसाय और कामकाज पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों में जांच और फैसला जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

सोने के जेवरात का दाम कैसे कैलकुलेट करता है जौहरी, समझिए फाइनल बिल का पूरा हिसाब

सोने के जेवरात खरीदने जाते हैं तो गोल्ड का रेट पता होने के बाद भी जौहरी की कैलकुलेशन समझ से बाहर होती है। हर जौहरी अलग तरह के चार्जेस लगाता है और लगता है कि जितनी कीमत चेक कर के आए थे उससे ज्यादा ही देनी पड़ गई। दरअसल सोने के जेवरात का दाम जीएसटी हॉलमार्किंग मेकिंग चार्जेस के साथ फाइनल तैयार होता है।

नईदिल्ली। भारत में शादी-ब्याह का मौका हो या कोई शुभ त्योहार, हर भारतीय घर में सोने के आभूषण खरीदने का प्रचलन वर्षों से चला आ रहा है। समय के साथ सोने के दाम में भी इजाफा हुआ है। हालांकि, जुलाई में पेश हुए यूनियन बजट के बाद से ही सोने की खरीदारी के लिए एक बार फिर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, 29 जुलाई को सोने का दाम 68131 रुपये प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। यही दाम बजट से पहले 22 जुलाई को 73,240 रुपये अपडेट हुआ था। यानी सोने 5000 रुपये तक सस्ता हो गया है। अब सवाल यह कि जब आप अपने शहर में गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी के लिए जौहरी के पास जाएंगे तो वह आपसे कितनी रकम अदा करने को कहेगा? दरअसल, सोने के आभूषण बेजने के लिए जौहरी का गणित समझा जाना जरूरी है। इस आर्टिकल में आपको उदाहरण के साथ सोने के आभूषण की फाइनल कीमत कैसे लगाई जाती है, बता रहे हैं- सोने की शुद्धता कैरेट के साथ मापी जाती है। सबसे शुद्ध सोना 24KT को माना जाता है। हालांकि, यहां ध्यान देने की बात ये है कि सोने के आभूषण कभी भी शुद्ध सोने से तैयार नहीं किए जा सकते हैं। 24KT गोल्ड की डेन्सिटी कम होती है। सोने के आभूषण 22K, 18K और 14K प्योरिटी वाले गोल्ड के साथ ही तैयार किए जा सकते हैं। जैसे-जैसे नंबर के साथ कैरेट कम होता है सोने की कीमत भी कम होती जाती है।

10 दिनों में टमाटर की कीमतों में आएगी नरमी, एनसीआर में एनसीसीएफ बेचेगी सस्ते टमाटर

परिवहन विशेष न्यूज

टमाटर के बढ़ते दामों के बीच उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि अगले सात से दस दिनों में टमाटर की कीमतों में नरमी आएगी। जोशी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा सोमवार से दिल्ली एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू करने के मौके पर बोल रहे थे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टमाटर के लगातार बढ़ती कीमत को थामने की पहल की है। दिल्ली-एनसीआर में उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रतिकिलो की दर से टमाटर उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में ही बाजार स्थिर हो जाएगा। सरकार विभिन्न मंडियों से 45 रुपये प्रतिकिलो की दर से टमाटर खरीदकर ढुलाई समेत सारा खर्च जोड़कर 60 रुपये प्रतिकिलो के भाव से बेचा जाएगा।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित रखने एवं उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बनाया है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने पर इस कोष का इस्तेमाल किया जाता है। बिचौलियों को दरकिनार कर इन वस्तुओं को सीधे किसानों से खरीदा जाता है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

दिल्ली में यहां से खरीद सकते हैं टमाटर

राजीव चौक एवं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, नेहरू प्लेस, कृषि भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोधी कालोनी, हौज खास प्रमुख कार्यालय, संसद मार्ग, आइएनए मार्केट, मंडी हाउस, कैलाश कालोनी, आईटीओ, साउथ एक्सटेंशन, मोती नगर, द्वारका, नोएडा (सेक्टर 14 और 76), रोहिणी एवं गुरुग्राम।

एनसीआर में 100 रुपये किलो बिक रहा टमाटर

एनसीसीएफ की वैन सब्सिडी दर पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। सहकारी समिति दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी सस्ती दर पर टमाटर बेचेगी। जोशी ने कहा कि टमाटर की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए यह पहल की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सब्जी विक्रेता गुणवत्ता और स्थान के आधार पर 70-100 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेच रहे हैं।

पीएसएफ के जरिए ग्राहकों को दी जाती है राहत

जोशी ने कहा कि केंद्र ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की है। उन्होंने कहा, "जब भी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और हम वस्तुओं की खरीद के लिए पीएसएफ का उपयोग करते हैं। ये आवश्यक वस्तुएं सीधे किसानों से खरीदी जाती हैं, जिससे बिचौलियों की लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर सामान मिल जाता है।" हालांकि इस मामले में पीएसएफ का उपयोग नहीं किया गया है। इन टमाटरों को सीधे मंडियों से खरीदा गया है।

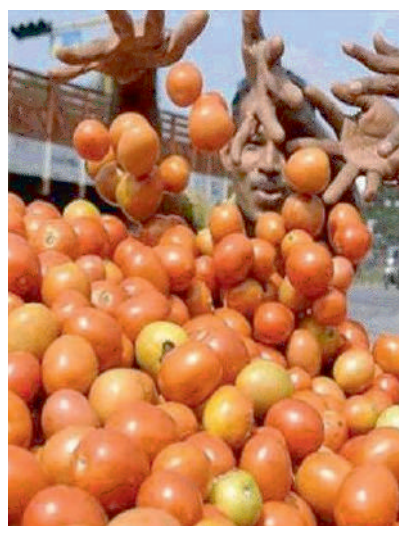

जेआरडी टाटा से किराये पर विमान लेते थे चीन के प्रधानमंत्री, एयर इंडिया समेत 14 कंपनियों की रखी थी नींव

JRD Tata 120th Birth Anniversary जेआरडी टाटा को भारतीय सिविल एविएशन का पितामह का कहा जाता है। वह भारत के पहले आधिकारिक पायलट थे। उन्होंने ही भारत की पहली विमानन कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने टीसीएस टाटा मोटर्स टाटा सॉल्ट और टाइटन जैसी सफल कंपनियों की नींव रखी। आइए जानते हैं कि किस तरह से चीन के प्रधानमंत्री भी उनसे विमान किराये पर लिया करते थे।

नई दिल्ली। आज चीन की अर्थव्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वह अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। लेकिन, एक वक्त जब ड्रैगन बेहद गरीब था, यहां तक कि भारत से भी ज्यादा। करीब सात दशक पहले चीन के प्रधानमंत्री चू ऐन लाई अक्सर विदेश यात्रा के लिए भारत से किराये पर विमान लेते थे। और उन्हें किराये पर विमान देने वाले शख्स थे, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा।

चू ऐन ने पहली दफा टाटा से विमान किराये पर लिया 1954 के मध्य में। तब वह भारत ही आने वाले थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मिलने। चू ऐन ने जेआरडी टाटा से पत्र से लिखकर किराये पर विमान उपलब्ध कराने की गुजारिश की। उस वक्त तक भारत सरकार के पास भी अपना विमान नहीं था। केंद्र सरकार में नागर विमानन विभाग जरूर था, लेकिन उसका सिर्फ सर्टिफिकेट, लाइसेंस आदि देने तक ही सीमित था।

उस समय विमानन सेवा के सर्वेसर्वा जेआरडी टाटा ही थे। एयर इंडिया बस बतौर निगम काम करता था। चीन के प्रधानमंत्री के लिए विमान उपलब्ध कराने की बात जेआरडी टाटा के पत्र से भी जाहिर होती है, जिसे उन्होंने नेहरू को लिखा था। इसमें टाटा ने लिखा था, 'मुझे खुशी है कि चीन के प्रधानमंत्री के लिए हमने जिस उड़ान की व्यवस्था की थी, वह ठीक रही। चीन के प्रधानमंत्री ने हमारी सेवा की प्रशंसा की'।

बचपन से ही उड़ान के शौकीन थे टाटा

जेआरडी टाटा की बचपन से हवाई उड़ानों में खास दिलचस्पी थी। उन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव भले ही 1932 में रखी, लेकिन टाटा साल 1919 में शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ा चुके थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हालांकि, उन्हें पायलट का आधिकारिक लाइसेंस लेने के करीब एक दशक का इंतजार करना पड़ा। उन्हें पायलट का लाइसेंस 1929 में मिला। वह पहले हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने यह तमगा हासिल किया था। उन्हें भारत में सिविल एविएशन के पितामह का दर्जा मिला।

जेआरडी 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। वह 1991 तक इस पद पर बने रहे। सरकार ने सिर्फ एक ही उद्योगपति को अब भारत रत्न से नवाजा है, और वह शख्स जेआरडी टाटा ही हैं।

कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी योजनाएं

जेआरडी अपने ग्रुप के कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा समझते थे। उन्होंने

कॉरपोरेट जगत में कई क्रांतिकारी सुधार किए। जेआरडी ने कुल 14 नई कंपनियों की शुरुआत की। इनमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट और टाइटन जैसी सफल कंपनियों के नाम शुमार हैं।

जेआरडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की तर्ज पर 1956 में टाटा प्रशासनिक सेवा (TAS) का आगाज किया। इसका मकसद टाटा ग्रुप में युवा प्रतिभाओं को ट्रेनिंग देकर लीडरशिप के लिए तैयार करना था।

टाटा ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई काम किए। टाटा ने ही सबसे पहले कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की कार्यसीमा तय की। अपने कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा और भविष्य निधि योजना की भी शुरू की। किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होने की स्थिति मुआवजा देने की पहल भी सबसे पहले उन्होंने ही की।

भगवान शिव ही सत्य, अनंत, अनादि, ओंकार शक्ति हैं

वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आगरा। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक खास महत्व है। आगरा के लिए सावन का महीना बेहद ही खास होता है। आगरा में सावन से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है, जिससे हर शहरवासी जुड़ता है और द्वितीय सोमवार की पूर्व रात्रि पर शहर में करीब 42 किमी की इस परिक्रमा लगाई जाती है, जिसमें लाखों शिव भक्त रातभर नंगे पैर चलकर शहर के चारों कोनों पर स्थित शिवालयों का जलाभिषेक कर पुण्य - लाभ कमाते हैं। इस दौरान पूरा शहर शिवमय होना प्रारंभ हो जाता है। वहीं, सावन के प्रत्येक सोमवार को आस्था का ज्वार उमड़ता है और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना बहुत शुभ और फालदायी माना जाता है। इस पूरे माह भगवान शिव शंकर की पूजा का विधान है।

सावन माह के पावन अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना ने समस्त शिव भक्तों व श्रद्धालुओं को पवित्सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव जी सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। शिव की शरण में आकर मन को खुराक मिलती है। मन को शिव भक्ति में सार्थक बनाएं। मन की मानना तो सिर्फ धोखा ही है, इसलिए मन को शिव में लगाएं। क्योंकि मान - अभिमान भक्ति में बांधक है, जहां अहंकार है। वहां शिव नहीं हो सकते। शिव को जीवन में स्थापित करने के लिए अपनी मैं को त्यागना पड़ता हैं। क्योंकि अहंकार वो दीमक है जो भक्ति को खा जाता है। हाथ पांव से दुनिया के सारे कामकाज करते हुए भी मन से शिव के साथ जुड़े हो। हर समय हर जगह शिव का अहसास बना रहे, शिव के प्रति ध्यान जुड़ा हो यही भक्ति है। उन्होंने कहा कि जो सारी दुनिया को चला रहा है, वह शिव स्वयं कितने शांत और मौन है और एक तरफ इंसान है जो अपनी चंचलता के वशीभूत होकर सिर्फ भटकाव में रहता है, इंसान चाहे तो शिव के साथ जुड़कर स्थिरता प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव सदैव हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करते है। पूरे भरे संसार में से सिर्फ़ हमें शिव भक्ति के लिए चुन लिया है। शिव ब्रह्मज्ञान प्रदान कर जहां परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वहीं छोटे - बड़े, ऊंच - नीच वाले भाव से भी मुक्त करते हैं, साथ ही प्यार और अपनत्व वाले भाव से मालामाल भी करते हैं। लेकिन आजकल क्षणिक देर के लिए मिली खुशी को हम सब आनंद मान रहे हैं, जबकि भक्त शिव को पाकर ही हम आनन्दित हो सकते है। श्री खुराना ने आगे कहा, शिव, ब्रह्मज्ञान प्रदान करने के साथ जो आध्यात्मिक नियम बताते है, उनके अनुसार चलकर हम सब अहम्से बच सकते हैं। वहीं मन को समर्पित कर देने पर हम वास्तविक शिव भक्ति का आनंद भी ले पाते हैं। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन को ज्ञानमय होकर गुजारे तो भक्ति पूर्ण है। इसलिए आओं हम सब मिलकर शिव के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुंदर बनाएं और हर खुशी को पाएं। इस पावन और पवित्र अवसर भगवान शिव जी आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें और देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि सदा सभी पर बनी रहे यही हमारी शिव से कामना हैं। इसी विचार के साथ एक बार पुनः भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार की सभी को शुभकामनाएं एवं उत्तर भारत के ऐतिहासिक भगवान शिव परिक्रमा महोत्सव में आये सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चार साल पूरे, स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एकरूपता लाने की पहल

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए चार साल पूरे हो चुके हैं। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। अब शिक्षा को भारतीय भाषाओं में देने पर जोर दिया जाएगा। सोमवार को नई दिल्ली के मानेकशां सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक संदेश के माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में आए बड़े सुधारों से जुड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को सोमवार को चार साल पूरे हो गए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पैटर्न में एकरूपता लाने की पहल की है। साथ ही नीति से जुड़ी पहलों को तेजी के साथ जमीन पर उतारने की भी अपील की है। इस अवसर पर राज्यों को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने का भी सुझाव दिया।

मानेकशां सेंटर में हुआ कार्यक्रम

नीति के चार साल पूरा होने के मौके पर मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम नाम से एक बड़ा आयोजन किया। इसमें देश की शीर्ष शिक्षाविदों के साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्यों और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नई दिल्ली के मानेकशां सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को वैसे तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित करना था, लेकिन संसद में व्यस्त होने के चलते वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने एक संदेश भेजकर सभी को संबोधित किया और कहा कि देश को 21वीं सदी के ज्ञान का खजाना बनाने के लिए वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय ज्ञान पर जोर

प्रधान ने नीति से जुड़ी अमलों को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से कार्य करने पर भी जोर दिया। राज्यों से नीति से जुड़ी अपनी अच्छी पहलों को एक-दूसरे के साथ साझा करने की सलाह दी। कार्यक्रम को शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉ. सुकांत मजूमदार ने भी संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया।

2020 में लागू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। जिसकी अब तक करीब दो सौ से ज्यादा सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। इस दौरान सोमवार को भी कई नई पहलों की घोषणा की गई। इसमें शिक्षा को भारतीय ज्ञान आधारित और भारतीय भाषाओं में देने पर जोर दिया गया।

संसद में गूंजा छात्रों की मौत का मुद्दा, 'जिम्मेदार आप.. जिम्मेदार आप' के लगे नारे

भारी बारिश के कारण ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। देसभर में इस हादसे की चर्चा है। इस हादसे को की गूंज सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भी गूंजा। वहीं इस हादसे को लेकर सभी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते दिखे।

नई दिल्ली। दिल्ली में जलभराव से कोचिंग में तीन छात्रों की मौत का मामला सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर अल्पकालिक चर्चा कराई गई तो लोकसभा में शून्यकाल में इसे उठाया गया। छात्र-छात्राओं की मुत्यु पर दुख तो सभी ने जताया, लेकिन जब जिम्मेदारी पर बात आई तो बजबजाते नालों और गंदे जलभराव में भी दलीय निष्ठा की धारा साफ दिखाई दी।

भाजपा ने कुछ शिकायतों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक सहित अधिकारियों ने शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। नालों की सफाई नहीं कराई गई, जिसकी वजह से घटना हुई। वहीं, आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया कि अधिकारी उपराज्यपाल के प्रभाव में हैं, सरकार के मंत्रियों के कहने पर भी नाला सफाई नहीं कराई। वहीं, कांग्रेस बहुत सधे अंदाज में चर्चा करती नजर आई। जलभराव के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने की बजाए बढ़ते को¨चग कल्चर पर घटना का ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया।

'सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी'

राज्यसभा में कार्य स्थगन के लिए नोटिस देने वालों में भाजपा सदस्यों के साथ ही आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी शामिल थीं। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे स्वीकार किया। चर्चा की शुरुआत भाजपा की ओर से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। कहा कि तीन छात्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों में आंसू क्या, माथे पर शिकन तक नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जून से 22 जुलाई तक शिकायतें और रिमाइंडर दिए गए कि उक्त कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही है। घटना हो सकती है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिकायतों के इस क्रम के बीच नौ जुलाई को इमारत को फायर की एनओसी दे दी गई।

'दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार'

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार जल निकासी और नालों की सफाई की बजाए प्रचार और वक्फ बोर्ड पर पैसा खर्च कर रही है। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्राइन ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की चर्चा मणिपुर, नीट, चीन के कब्जे जैसे मुद्दों पर कराई जाएगी। यही बात डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कही। आप का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि एलजी फैसले लेते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोचिंग और लाइब्रेरी को रेगुलेट केंद्र सरकार करेगी। यह संस्थान 25-30 साल से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अधिकारी सिर्फ एलजी की बात सुनते हैं। मंत्री अफसरों से कहते रहे, लेकिन उन्होंने नाला सफाई की बात नहीं सुनी।

'आप सरकार काम नहीं कर रही, सत्ता भोग रही'

कांग्रेस सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी तरह की चर्चा नीट, चीन, मणिपुर आदि पर कराने की मांग की। कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण कर दिया है। रोजगार की कमी है। सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। स्कूल-कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसलिए कोचिंग संस्थान बढ़े हैं। इसी कारण यह घटना हुई है। वहीं, लोकसभा में शून्यकाल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे को उठाया और कहा आप सरकार काम नहीं कर रही, सत्ता भोग रही है। समिति बनाकर घटना की जांच होनी चाहिए।

'जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए'

कांग्रेस के शशि थरूर ने पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति की मांग उठाई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने निष्पक्ष जांच कराने की बात कही तो अखिलेश यादव ने भी जोर दिया कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों ने ही एनओसी दी होगी। यूपी में जैसे अवैध इमारतों पर बुल्डोजर चलता है, वैसा यहां भी चलेगा या नहीं? कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि को¨चग संचालक माफिया की तरह काम कर रहे हैं।

कोचिंग के लिए स्पष्ट है कानून, राज्यों को लेनी होगी जिम्मेदारी

प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस चर्चा पर दोनों सदनों में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक समय-समय पर कई बार कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शिका राज्यों को भेजी गई है। इस वर्ष की जनवरी में एडवाइजरी भेजी थी। अगर उसका पालन होता तो यह घटना नहीं होती। कोचिंग संस्थान पर सवाल उठाए जाने पर किसी का नाम लिए बिना बोले कि कुछ लोगों के मन में मैकालेवाद का भूत अभी तक चढ़ा हुआ है। प्रधान ने कहा कि कोचिंग सेंटर संचालन के लिए कानून स्पष्ट है। राज्यों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार शिक्षा में सुधार चाहती है। इसके लिए समिति बनाई है, सभी सांसद उसमें सुझाव दें। वहीं, नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं गिनाईं और कहा कि मोदी सरकार पूरी पारदर्शिता चाहती है और हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।

रोडवेज बस के चालक-परिचालक अब लगाएंगे नेमप्लेट

परिवहन विशेष न्यूज

मैनपुरी। मार्ग पर रोडवेज बस ले जाने वाले चालक और परिचालक अब नेमप्लेट भी लगाएंगे। बस में मौजूदगी के समय उनके लिए ड्रेस पहनना भी जरूरी होगा। चालक और परिचालक के नेमप्लेट लगाने से यात्रियों की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

मार्ग पर रोडवेज बस ले जाने वाले सभी चालक और परिचालक के लिए परिवहन मुख्यालय ने ड्रेस पहनने के साथ ही ड्रेस पर नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव परिवहन ने इस संबंध में निर्देश जारी करके कड़ाई से पालन कराने को कहा है। मार्ग में बसों को चेक करने वाले सचल दल प्रभारियों को भी चालक और परिचालक की ड्रेस के साथ नेम प्लेट भी चेक करने की हिदायत दी है।

रोडवेज बस में यात्रा करते समय यात्रियों को होने वाली परेशानी के बाद उनको शिकायत करने के लिए चालक और परिचालक का नाम पता करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। चालक और परिचालक के आचरण की शिकायत करने में अब नेम प्लेट का सहारा उनको मिलेगा। लोगों का कहना है कि इससे चालक और परिचालक की गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।

प्रमुख सचिव के पत्र के बाद आरएम कार्यालय से भी इस संबंध में निर्देश मिले हैं। निर्देश का पालन कराने के लिए सभी चालकों और परिचालकों सहित बस संचालन प्रभारी को भी सूचना दे दी गई है।

संजीव कुमार, एआरएम

पुणे आरटीओ में शुरू हुआ रोड सेफ्टी एंड एक्सपीरियंस लैब, जानें क्या है इसकी खासियत

ट्रैफिक को लेकर जागरूकता पैदा करने के मकसद से, पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने अपने लर्नर लाइसेंस विभाग के अंदर एक रोड सेफ्टी एंड एक्सपीरियंस लैब शुरू की है।

लर्नर लाइसेंस आवेदकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और ट्रैफिक को लेकर जागरूकता पैदा करने के मकसद से, पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने अपने लर्नर लाइसेंस विभाग के अंदर एक 'सड़क सुरक्षा और अनुभव प्रयोगशाला' (रोड सेफ्टी एंड एक्सपीरियंस लैब) शुरू की है। यहां हर आवेदक को पहले यातायात जागरूकता का टेस्ट देना होता है। और फिर ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट देनी होती है।

राज्य परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'क्रूजिंग सेफ' नाम के एक निजी संगठन की मदद ले रहा है। 'क्रूजिंग सेफ' ने पुणे आरटीओ में यह 'सड़क सुरक्षा और अनुभव प्रयोगशाला' शुरू की है। उम्मीदवारों को वाहन लाइसेंस के लिए आरटीओ लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने से पहले तीन लेवल के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। राज्य के तीन आरटीओ, जिसमें पुणे आरटीओ भी शामिल है, में ऐसे 'एक्सपीरियंस लैब' शुरू किए गए हैं।

पुणे की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड़ ने कहा, ₹पिछले कुछ दिनों में पुणे शहर और जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए न सिर्फ ड्राइवरों को परामर्श देने बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। पुणे आरटीओ में शुरू की गई इस प्रयोगशाला के जरिए, लर्नर लाइसेंस लेने आने वाले उम्मीदवारों को तीन स्तरों के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। पहले लेवल पर, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल पर, ट्रैफिक नियमों के आधार पर सावल किए जाते हैं। और तीसरे लेवल पर एक वीडियो दिखाया जाता है।"

उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार में लगभग 10 से 12 उम्मीदवार टेस्ट दे सकते हैं। इससे पहले, आरटीओ मोटर वाहन निरीक्षक उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद, वीडियो गाइडेंस के साथ असली टेस्ट शुरू होती है। इसमें 20 सवाल होते हैं और हर दिन कम से कम 50 उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लर्नर लाइसेंस आवेदक किरण सालोखे ने कहा, ₹मैं इस एक्सपीरियंस लैब में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए टेस्ट से गुजरा और यह बहुत अच्छा अनुभव रहा। ट्रैफिक से जुड़े नियमों और विनियमों के बारे में कई सवाल पूछे गए। और मुझे इस टेस्ट के जरिए कई नई चीजें पता चलीं।"

पुणे आरटीओ के केंद्र प्रबंधक गणेश ओकाटे ने कहा, ₹पुणे आरटीओ में शुरू की गई इस लैब द्वारा आयोजित टेस्ट उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यह टेस्ट ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों की बेहतर समझ देता है। संबंधित संगठन को यह प्रतिक्रिया मिल रही है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। इसमें उम्मीदवारों का लगभग 10 से 15 मिनट का समय भी लगता है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नागरिकों के पास सुरक्षित सड़क परिवहन हो।"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023